नई दिल्ली
26 अगस्त, 2026 बुधवार
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 146

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

सूर्यकुमार ने अब भी नही छोड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीदें 07

पीएम मोदी की नई बीजेपी टीम को नसीहत- जीत पर मत इतराओ, जनता से जुड़े रहो

नितिन नवीन के नेतृत्व वाली नई राष्ट्रीय टीम से पहली मुलाकात

वेब वार्ता, नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन को मजबूत करने और जनता से लगातार जुड़े रहने पर विशेष जोर दिया। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने नई टीम को चुनावी सफलताओं से संतुष्ट होकर नहीं बैठने की नसीहत दी और कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर लोगों की नब्ज समझते हुए लगातार सक्रिय रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व वाली नई राष्ट्रीय टीम के सदस्यों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 65 नए पदाधिकारियों में शामिल सदस्यों से उनके राजनीतिक और संगठनात्मक सफर को लेकर भी चर्चा की। बैठक में पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारी और विभिन्न राज्यों की इकाइयों के प्रमुख भी मौजूद रहे।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने पदाधिकारियों से कहा कि संगठन की मजबूती का आधार जनता और पार्टी कार्यकताओं के साथ निरंतर संवाद है। उन्होंने विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और आम लोगों की समस्याओं व अपेक्षाओं को समझने पर जोर दिया।

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी नई टीम के सदस्यों से बातचीत करते हुए जनता और पार्टी कार्यकताओं के साथ संबंध मजबूत करने की अपील की। खासतौर पर उन राज्यों में संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया, जहां बीजेपी सत्ता में है।

बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। इनमें उपाध्यक्ष राम माधव और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, महासचिव स्मृति ईरानी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब, महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष तथा केंद्रीय मंत्री और पार्टी कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी कहा कि संगठनात्मक बैठकों का उद्देश्य नए विचारों और दृष्टिकोण के माध्यम से पार्टी को मजबूत करना तथा जनता के साथ जुड़ाव को और गहरा बनाना है।

17 अगस्त को घोषित हुई थी नई टीम

नितिन नवीन के नेतृत्व वाली बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा 17 अगस्त को की गई थी। नई टीम में कुल 65 पदाधिकारी शामिल हैं, जिनमें 51 नए चेहरे हैं। नई राष्ट्रीय टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली औपचारिक बातचीत मानी जा रही है।

सरकारी कबाड़ से खोज लिया 6000 करोड़ का खजाना

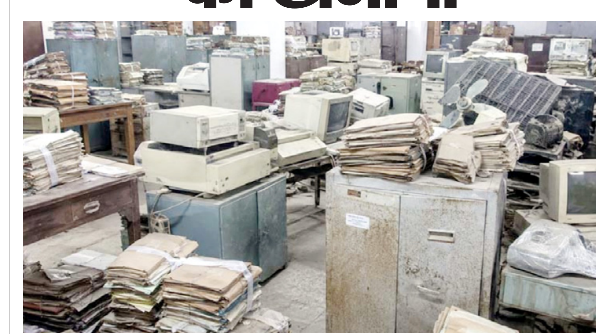

नई दिल्ली। सरकारी दफ्तरों में लंबे समय से धूल फांक रही पुरानी फाइलों, खराब मशीनों और अनुपयोगी सामान को जब केंद्र सरकार ने एक मूल्यवान संपत्ति के तौर पर देखा, तो एक अभूतपूर्व आर्थिक और प्रशासनिक उपलब्धि सामने आई।

पिछले छह वर्षों के दौरान चलाए गए विशेष स्वच्छता और कबाड़ निस्तारण अभियानों के माध्यम से, केंद्र सरकार ने न केवल 6,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम राजस्व जुटाया है, बल्कि 1,233 लाख वर्ग फीट (यानी 12.33 करोड़ वर्ग फीट) की महत्वपूर्ण जगह भी खाली कराई है। इस खाली हुई जगह की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह क्षेत्रफल लगभग 29 भारत मंडपम या दिल्ली एयरपोर्ट के 21 टर्मिनल-3 के कुल निर्मित क्षेत्र के बराबर है। अनुपयोगी कबाड़ को हटाकर सरकारी विभागों ने न केवल बड़ी कमाई की है, बल्कि अपने कार्यस्थलों को अधिक खुला, व्यवस्थित और आधुनिक रूप भी दिया है।

यह उपलब्धि दशार्ती है कि आम तौर पर बेकार समझे जाने वाले सरकारी सामान को अब कमाई के एक बड़े स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। 6,000 करोड़ की यह रकम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यह भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के लिए तय 20,193 करोड़ के बजट का लगभग 30 प्रतिशत है। यह राशि आयुष मंत्रालय जैसे किसी बड़े सरकारी विभाग के सालाना बजट के लगभग बराबर है, और यह सब केवल बेकार हो चुके सरकारी सामान को हटाकर जुटाई गई है। सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में दशकों से विभिन्न प्रकार का सामान जमा होता रहता है झ जैसे टूटा-फूटा या अनुपयोगी फर्नीचर, पुरानी मशीनरी, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फाइलें और ऐसी ही दूसरी चीजें जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं होती। अक्सर देखा गया है कि एक बार जब कोई चीज सरकारी स्टोर रूम, यार्ड या दफ्तर के परिसर में पहुंच जाती है, तो वह सालों-साल वहीं पड़ी रहती है।

जगह को खाली कराएं

इस विशेष सफाई अभियान का मुख्य उद्देश्य इसी स्थिति को बदलना था। विभागों से यह अपेक्षा की गई कि वे ऐसे सामान की पहचान करें जो अब उनके काम का नहीं रहा है, उसे निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत हटाएं और इस प्रकार सरकारी कीमती जगह को खाली कराएं। इस पहल के दो महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष लाभ हुए हैं। पहला, जो सरकार के वित्तीय खातों में स्पष्ट रूप से दिखता है 6,000 करोड़ की उल्लेखनीय कमाई। दूसरा, जो जमीन पर महसूस किया जा सकता है। 12.33 करोड़ वर्ग फीट की मूल्यवान जगह की उपलब्धता।

संक्षिप्त वार्ता

ग्वालियर कृषि के क्षेत्र में पंजाब व हरियाणा से भी आगे पहुँचेगा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा ग्वालियर का नाम लेते ही गौरव की अनुभूति होती है। ग्वालियर की जितनी प्रसिद्धि संगीत सम्राट तानसेन से है, उतनी ही प्रसिद्धि यहाँ की गजक, किसान और जवानों से भी है। शिक्षा, रक्षा, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और दुग्ध उत्पादन में ग्वालियर संभाग पूरे प्रदेश में अग्रणी है। ग्वालियर कृषि के क्षेत्र में भी पंजाब और हरियाणा से आगे पहुँचेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर जिले के डबरा तहसील प्रांगण में बलराम कृषि महोत्सव के तहत आयोजित हुए कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत किसानों की सेवा व समृद्धि के लिये बलराम कृषि महोत्सव मनाए जा रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह भी उपस्थित थे।

प्रदेश में निवेश का महाभियान लगातार बढ़ रहा है आगे

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश का महाभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। जुलाई में आदित्य टेक्नो कंपनी, लियोन इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इसी प्रकार पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए लागत की दो नई इंडस्ट्रीज का शुभारंभ भी किया गया है। यह इंडस्ट्री राजस्थान से मध्यप्रदेश आकर अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं।

ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए दिल्ली में आयोजित रोड शो में लगभग 5000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और अहमदाबाद में हुए रोड शो में 8 हजार 635 करोड रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सभी क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के समाधान में 1712 मामलों का हुआ समाधान

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय का समाधान कार्यक्रम, जो एक विशेष लोक अदालत और मध्यस्थता पहल है, बेहद सफल रहा है। 21 से 23 अगस्त तक चले इस तीन दिवसीय आयोजन में कुल 1,712 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। पक्षकारों की आपसी सहमति और समझौते के परिणामस्वरूप समाप्त हुए इन मामलों में 240.94 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जो इस कार्यक्रम की व्यापक सफलता को दशार्ती है।

इस समाधान कार्यक्रम की शुरूआत इसी साल 21 अप्रैल को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों को न्यायालय की लंबी और जटिल प्रक्रिया के बजाय मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलझाना था। इस विशेष लोक अदालत में मामलों को लाने से पहले, पक्षकारों और उनके वकीलों के साथ गहन बातचीत के

माध्यम से समझौते की कोशिशें की गई थीं, ताकि त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में कुल 3,285 मामले सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से पहले दिन 402, दूसरे दिन 350, और तीसरे दिन 912 मामलों का समाधान किया गया। इस प्रकार, लोक अदालत के माध्यम से कुल 1,664 मामले सुलझे, जबकि 48 मामलों का निपटारा मध्यस्थता के जरिए हुआ, जिससे कुल 1,712 विवादों का समाधान संभव हो सका। लोक अदालत की पीठों की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने की। इनमें मुख्य रूप से वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, सड़क हादसों से जुड़े मुआवजे के मामले, जमीन अधिग्रहण और मुआवजा, कर, सेवा और श्रम संबंधी मामले शामिल थे। इस संस्थागत पहल को सफल बनाने के लिए न्यायाधीशों ने शनिवार और रविवार को भी काम किया। इस पहल से न केवल लोगों के पैसे और समय की बचत हुई, बल्कि न्यायालय का बहुमूल्य समय भी उन मामलों के लिए बचाया जा सका जिनकी सुनवाई अनिवार्य है।

हिमाचल में भरभराकर गिरा पहाड़ का हिस्सा, सड़क पर फैला मलबा-पत्थर

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मंगलवार को भारी बारिश के बीच भूस्खलन की घटना सामने आई। भरमौर के कोडला-उरई सड़क मार्ग पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। इसके बाद सड़क पर मलबा और बड़े पत्थर फैल गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पहाड़ का हिस्सा गिरते देख आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात रही कि भूस्खलन की चपेट में कोई वाहन या व्यक्ति नहीं आया। हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है।

लगातार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। राज्य में बारिश के चलते करीब 125 सड़कें प्रभावित हुई हैं। इसका सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में बताया जा रहा है। कई स्थानों पर सड़कें बाधित होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 29 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। 30 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसी अवधि में कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बना हुआ है।

पिछले 8 सालों में भारत में स्कूलों की संख्या घटी, 11 करोड़ बच्चे हुए बाहर

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने हाल ही में स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में खराब बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को उठाया। अभियान में सरकारी स्कूलों की घटती संख्या, छात्रों के नामांकन में गिरावट और निजी स्कूलों पर बढ़ती निर्भरता को उजागर किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 8 सालों में भारत में स्कूलों की संख्या में कमी आई है। इसी दौरान छात्रों के नामांकन में भी गिरावट आई, हालांकि छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है। देश में 2018-19 में स्कूलों की कुल संख्या 15.5 लाख थी, जो 2025-26 में घटकर 14.6 लाख रह गई। छात्रों के नामांकन में भी कमी आई है। छात्रों का नामांकन

2018-19 में 26 करोड़ से घटकर 2025-26 में यह 24.7 करोड़ रह गया है। वहीं, छात्र-शिक्षक अनुपात 2018-19 में 27 छात्रों पर एक शिक्षक से सुधरकर 2025-26 में 24 छात्रों पर एक शिक्षक हो गया है। यह सुधार मुख्य रूप से छात्रों की संख्या घटने की वजह से हुआ है, न कि शिक्षकों की संख्या बढ़ने के कारण। 2025-26 में करीब 31 फीसदी पात्र बच्चों का स्कूलों में नामांकन नहीं था यानी 3 से 17 साल की आयु के करीब 11.1 करोड़ बच्चे स्कूल शिक्षा से बाहर थे। यह स्थिति पिछले 8 सालों से बनी हुई है। अधिकांश सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। करीब 99 फीसदी सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा, 94 फीसदी में बिजली और 96 फीसदी में शौचालय उपलब्ध हैं।

हालांकि, डिजिटल सुविधाओं के मामले में स्थिति अभी कमजोर है। केवल 25 फीसदी स्कूलों में कंप्यूटर, 16 फीसदी में प्रोजेक्टर और 6 फीसदी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या में आई गिरावट के साथ शिक्षा बजट में भी कमी आई है।

सांबा में निमार्णाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, एक की मौत

सांबा। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में निमार्णाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घटना विजयपुर के जख इलाके में निर्माण कार्य के दौरान हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना के संबंध में मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, कि फ्लाईओवर के निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान निमार्णाधीन ढांचे का एक हिस्सा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। वहां मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। राहत एवं बचाव कार्य चलाकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि तीन घायलों का इलाज जारी है।

कंगना और अभिजीत के बीच अंग्रेजी पर छिड़ी जंग

नई दिल्ली। अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री और अब सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर एक नए विवाद को जन्म दिया है। इस बार उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ अपनी अंग्रेजी बोलने की शैली की तुलना की है, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। कंगना ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक स्टोरी साझा की, जिसमें उन्होंने दीपके के अंग्रेजी में दिए गए एक बयान की रील के साथ अपना कुछ साल पुराना अंग्रेजी का भाषण भी दिखाया। उनके पुराने भाषण में कंगना फिल्म उद्योग में एक महिला कलाकार के रूप में अपनी छवि पर बात करती नजर आती हैं। साझा की गई रील में उन्होंने लिखा, 12वीं पास कंगना रनौत बनाम बोस्टन यूनिवर्सिटी के सीजेपी के दीपके का अंग्रेजी स्तर। एक शानदार है तो वहीं दूसरे को रीबूट की जरूरत है।

इसरो लॉन्च वाहन और सैटेलाइट निर्माण का काम अब निजी हाथों में देगा

वर्तमान समय में भारत में करीब 450 अंतरिक्ष स्टार्टअप कर रहे कार्य

वेब वार्ता, नई दिल्ली

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अब अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। इसके तहत वह अनुसंधान, विकास और बड़े अंतरिक्ष मिशनों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि लॉन्च वाहनों और नियमित उपग्रहों के निर्माण का काम निजी क्षेत्र की कंपनियों या पीएसयू को सौंपा जाएगा। अगले साल भारत मानवयुक्त ऑर्बिटल अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और 2035 तक उसकी योजना ह्यभारतीय अंतरिक्ष स्टेशनह्ण तैयार कर लेने की है। वह 2040 तक भारतीय नागरिक के चंद्रमा पर उतारने का ख्वाब भी बुन रहा है, जिसे पूरा करने के लिए इस बदलाव से मजबूती मिलेगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान समय में भारत में करीब 450 अंतरिक्ष स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। अपस्ट्रीम खंड में अंतरिक्ष संपत्तियों के विकास, परीक्षण, प्रक्षेपण, संचालन और निगरानी सुनिश्चित करने वाली सभी गतिविधियां, उत्पाद और बुनियादी ढांचा आता है, जबकि डाउनस्ट्रीम खंड में उपग्रहों पर निर्भर वे सभी अनुप्रयोग, सेवाएं एवं उपकरण शामिल होते हैं, जो इस कारोबार की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन गोयनका ने कहा था कि इसरो कोई प्रक्षेपण यान तैयार नहीं करेगा

और न ही किसी लॉन्च वाहन का निर्माण करेगा। यह सब काम अब निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाएंगे।

अग्निकुल कॉसमॉस के सह-संस्थापक और मुख्य परिचालन अधिकारी मोइन एसपीएम ने कहा कि यह इसरो और निजी क्षेत्र के एक साथ काम करने की रणनीति का अगला चरण है। इसके तहत अब इसरो का जोर अनुसंधान और उससे जुड़ी प्रौद्योगिकी को विकसित करने पर रहेगा, जबकि निजी कंपनियां सैटेलाइट निर्माण और परिचालन क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाएंगी। इस बदलाव को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट नियामकीय निगरानी, सुरक्षा जांच करने के साथ ऐसे सुरक्षा उपाय भी करने होने चाहिए जिससे महत्त्वपूर्ण बौद्धिक संपदा एवं विनिर्माण क्षमता देश में ही बनी रहे।

नई कहानी लिखी जायेगी

भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट (सेवानिवृत्त) ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहीं निजी कंपनियों की हालिया सफलताओं ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर भारत की क्षमताओं का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिससे निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को यह अच्छा सकारात्मक संकेत मिला है कि भारतीय कंपनियां नवाचार से आगे बढ़कर अब अंतरिक्ष अभियानों को पूरा कर सकती हैं। फिलहाल सरकार का ध्यान अपस्ट्रीम क्षमताओं पर केंद्रित है, जबकि अगले चरण में डाउनस्ट्रीम में भी सफलता की नई कहानी लिखी जाएगी।

सुहोरा टेक्नॉलजीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह-संस्थापक कृष्णु आचार्य ने कहा कि जैसे-जैसे अधिक उपग्रह कक्षा में पहुंचेंगे, उनसे उपलब्ध डेटा का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक गहराई से उसका अध्ययन न किया जाए और यहीं से डाउनस्ट्रीम कंपनियों की भूमिका मजबूत होगी, जो भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व में वृद्धि का कारण बनेंगी।

संपादकीय

मंदिर पर्यटन की प्राथमिकताएं

पिछले तीन साल में हिमाचल के प्रमुख 36 मंदिरों ने 419.88 करोड़ बटोर कर यह साबित कर दिया कि तीर्थाटन से हिमाचल बहुत कुछ कर सकता है। बेशक प्रतिवर्ष 150 करोड़ की मंदिर कमाई को हम अच्छी योजनाओं-परियोजनाओं से बढ़ा सकते हैं, यदि धार्मिक पर्यटन को विस्तृत भूमिका में देखा जाए। एक अनुमान के अनुसार हिमाचल में यात्रा की 80 फीसदी वजह केवल तीर्थाटन है, लेकिन हमारा टूरिस्ट मैप इसकी गवाही नहीं देता। इसके लिए अहम है मंदिर व्यवस्था में सुधार तथा प्रशासनिक व वित्तीय ढांचे में सुधार। समस्त मंदिरों का रखरखाव, उनका योजना व बजट आकार तथा कॉडर की समानता या एक रूपता नहीं होगी, तो आय-व्यय के बीच केवल स्वार्थ सिद्धियां ही होंगी। आवश्यक यह है कि एक केंद्रीय ट्रस्ट तथा मंदिर व्यवस्था के लिए मंदिर प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण बने। उदाहरण के लिए तीन साल की मंदिर कमाई अगर 419.88 करोड़ है तो इसी के अनुरूप खर्च का हिसाब एकीकृत नहीं है। अधिकतर मंदिर ट्रस्ट आय-व्यय का सबसे बड़ा भाग या तो अनावश्यक प्रशासनिक खर्चों, कर्मचारी तनख्वाहों या अनुत्पादक खर्चों में होता है। कई तरह के शैक्षणिक संस्थान मंदिर ट्रस्ट चला रहे हैं, तो यह सही नहीं है। मंदिर की आय का एक हिस्सा मंदिर के विस्तार या आय बढ़ाने के लिए होना चाहिए। अगर मंदिर प्राधिकरण के तहत मंदिरों की आय-व्यय का सांचा तय हो तो न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि योजनाओं-परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन के साथ जुड़ जाएगा। इतना ही नहीं मंदिर आय को बढ़ाने के लिए कुछ साझे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं।

मसलन अगर दियोटसिद्ध के रोट व ज्वालामुखी के पेड़ों को तमाम मंदिरों के प्रसाद से जोड़ा जाए या धूप व गिफ्ट आइटमों का उत्पादन भी तय हो तो मंदिरों की सामूहिक आय बढ़ेगी। मंदिरों की आय से कोंकण रेलवे की तर्ज पर चिंतपूर्णी, दियोटसिद्ध, कांगड़ा, चामुंडा व अन्य मंदिर परिसर जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं भाषा-संस्कृति विभाग अगर मंदिर परिसरों को कला केंद्रों के रूप में विकसित करे, तो सैकड़ों कलाकारों को आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे। हर मंदिर में आधुनिक सभागार के अलावा आर्ट म्यूजियम तथा ट्रेड सेंटर विकसित किए जा सकते हैं। मंदिर परिसर को धार्मिक नगर विकास की योजना से जोडकर शहरी आर्थिकी विकसित की जा सकती है। मसलन बड़े मंदिरों के आठ-दस किलोमीटर क्षेत्र की धार्मिक शहर विकास योजना पर काम करना होगा, ताकि इन क्षेत्रों को मंदिर आय से जोडकर नई आर्थिकी विकसित की जा सके। मंदिरों की क्षमता का विस्तार अगर विविध संभावनाओं के अनुरूप करें, तो हिमाचल पांच हजार करोड़ की आर्थिकी विकसित कर सकता है। मंदिरों के साथ अलग-अलग टूरिस्ट सर्किट तथा उत्सव व सांस्कृतिक समागमों का एक वार्षिक कैलेंडर जोड़ना होगा। इतना ही नहीं मंदिर पर्यटन के प्रारूप में धरोहर पर्यटन को भी जोड़ा जा सकता है। मंदिरों में श्रद्धालुओं के कई वर्ग आ रहे हैं अतः दर्शन व्यवस्था के अलावा आकर्षण बढ़ाने के लिए सीमांत क्षेत्रों के पर्यटन को अहमियत देनी होगी। उदाहरण के लिए पांवटा साहिब व ऊना में सिख पर्यटन की अहमियत बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास करने होंगे। वाराणसी पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन को अपने टूअर पैकेज में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का आग्रह किया है। वाराणसी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन का एक उत्तम उदाहरण है जहां साधारण से हाई एंड टूरिस्ट सुविधाओं के खाके पूर्ण हैं। अगर हमें वाराणसी की तरह प्रयास करने हैं, तो प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन, विकास, अधोसंरचना और सुविधाओं में निखार लाना होगा। विडंबना यह है कि कुछ वर्ष पूर्व ज्वालामुखी में म्यूजिकल फाउंटेन स्थापित हुआ, लेकिन यह आज तक चला ही नहीं।

लॉस एंजिलिस 2028 की तैयारी से बदल रहा भारतीय क्रिकेट का चेहरा

भारतीय क्रिकेट अब उस दौर में पहुंच गया है, जहां देश के पास केवल एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय टीम नहीं, बल्कि एक साथ कई स्तरों पर मुकाबला करने लायक खिलाड़ियों की लंबी कतार मौजूद है। आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा बदलाव दिखाई दे सकता है, जिसकी कल्पना कुछ दशक पहले करना भी मुश्किल था। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के दबाव, खिलाड़ियों के बढ़ते कार्यभार और 2028 के लॉस एंजिलिस ओलिंपिक में क्रिकेट की वापसी ने भारतीय क्रिकेट को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर किया है। इसी दिशा में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का टैलेंट पूल तैयार करने की योजना भारतीय क्रिकेट के भविष्य की तस्वीर बदल सकती है।

लॉस एंजिलिस ओलिंपिक 2028 भारतीय क्रिकेट के इस बदलाव की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। क्रिकेट को ओलिंपिक में शामिल किए जाने के बाद यह खेल केवल पारंपरिक टेस्ट और द्विपक्षीय सीरीज तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के लिए ओलिंपिक में पदक जीतना अब प्रतिष्ठा का सवाल भी होगा। ऐसे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने ऐसी टीम तैयार करने की चुनौती होगी, जो विश्व कप और द्विपक्षीय क्रिकेट के साथ–साथ ओलिंपिक जैसे बड़े मंच पर भी देश का प्रतिनिधित्व कर सके।

यही कारण है कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों का एक बड़ा और मजबूत समूह तैयार करना जरूरी हो गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का कार्यक्रम लगातार व्यस्त होता जा रहा है। एक तरफ टेस्ट और वनडे क्रिकेट है, दूसरी तरफ टी20 क्रिकेट का विस्तार हो रहा है। इसके साथ आईपीएल ने भारतीय खिलाड़ियों की संख्या और गुणवत्ता दोनों को नई ऊंचाई दी है। अब स्थिति यह है कि घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से लगातार ऐसे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चुनौती के लिए तैयार दिखाई देते हैं।

भारत के पास प्रतिभाओं की यह ताकत उसकी सबसे बड़ी क्रिकेट संपत्ति बन चुकी है। आज किसी एक खिलाड़ी के चोटिल होने या आराम लेने पर टीम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ने की स्थिति नहीं है। बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी, स्पिन, विकेटकीपिंग और ऑलराउंडर के रूप में भारत के पास विकल्पों की लंबी सूची है। यही गहराई भारतीय क्रिकेट को दुनिया की दूसरी टीमों से अलग बनाती है।

यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनके साथ सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी अलग–अलग परिस्थितियों में टीम को मजबूती देने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर टीम के संतुलन को बेहतर बनाते हैं। दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और मयंक यादव जैसे तेज गेंदबाज भारत के पास मौजूद गेंदबाजी की विविधता को दिखाते हैं।

स्पिन विभाग भी भारत की बड़ी ताकत है। कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज अलग–अलग तरह की परिस्थितियों में प्रभाव डाल सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उपयोगी विकल्प देते हैं। यही गहराई बताती है कि भारतीय क्रिकेट अब केवल गिने–चुने सितारों पर निर्भर नहीं है। अगर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में टकराव की स्थिति बनती है और भारत को एक ही समय में अलग–अलग प्रतियोगिताओं में टीमें उतारनी पड़ती हैं, तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी परीक्षा के साथ–साथ बड़ी उपलब्धि भी होगी। इसका अर्थ होगा कि भारत के पास इतने अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मौजूद हैं कि दो अलग–अलग टीमों को मैदान में उतारने की क्षमता विकसित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में किसी टीम को कमजोर या दूसरी श्रेणी की टीम मानने के बजाय दोनों टीमों को भारतीय क्रिकेट की वास्तविक गहराई का प्रतिनिधि माना जा सकेगा।

यह बदलाव अचानक नहीं आया है। पिछले दो दशकों में भारतीय क्रिकेट की संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आईपीएल ने युवा खिलाड़ियों को दुनिया के शीर्ष क्रिकेटरों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और दबाव में प्रदर्शन करने का अवसर दिया। घरेलू क्रिकेट की मजबूत व्यवस्था ने भी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। नतीजा यह हुआ कि छोटे शहरों और अलग–अलग राज्यों से खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने लगे। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी इस बदलाव का प्रतीक हैं। पहले राष्ट्रीय टीम तक पहुंचने का रास्ता बेहद लंबा और सीमित अवसरों वाला था। अब प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के सामने घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं के जरिए अपनी क्षमता साबित करने के कई मंच हैं। इससे भारतीय क्रिकेट का दायरा महानगरों से निकलकर देश के छोटे शहरों और कस्बों तक फैल गया है। भारत की क्रिकेट लोकप्रियता ने भी इस प्रक्रिया को गति दी है। देश में क्रिकेट केवल खेल नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। करोड़ों प्रशंसकों की रुचि, आईपीएल की सफलता और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की लगातार मजबूत होती स्थिति ने इस खेल को नई आर्थिक ताकत दी है। इसका सीधा लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है और क्रिकेट का बुनियादी ढांचा लगातार मजबूत हो रहा है। भारत की हाल की अंतरराष्ट्रीय कामयाबियां भी इस बदलाव की पुष्टि करती हैं। बड़े टूर्नामेंटों में भारत का प्रदर्शन, दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों का लगातार सामने आना और घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा का बढ़ना इस बात के संकेत हैं कि भारतीय क्रिकेट की नींव मजबूत हो चुकी है। अब लक्ष्य केवल मैच जीतना नहीं, बल्कि लंबे समय तक विश्व क्रिकेट में शीर्ष स्थान बनाए रखना है।

लॉस एंजिलिस ओलिंपिक इस लक्ष्य को और बड़ा कर देता है। ओलिंपिक में क्रिकेट के शामिल होने से भारत के सामने अपने क्रिकेट प्रभाव को एक नए वैश्विक मंच पर साबित करने का अवसर होगा। इसके लिए ऐसी टीम चाहिए होगी, जिसमें अनुभव और युवाओं का सही संतुलन हो। शीर्ष खिलाड़ियों को लगातार हर मुकाबले में उतारने के बजाय उन्हें महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं के लिए तरोताजा रखना भी जरूरी होगा। इसी कारण बड़ा टैलेंट पूल भारत की रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है। भविष्य में केंद्रीय अनुबंध व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ विशेषज्ञ टी20 खिलाड़ियों के लिए अलग श्रेणी बनाने पर विचार संभव है। तेज गेंदबाजों के कार्यभार को ध्यान में रखकर जिस तरह विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी तरह टी20 क्रिकेट में विशेषज्ञता रखने वाले खिलाड़ियों को भी अलग तरीके से तैयार किया जा सकता है। हालांकि दो मजबूत टीमों की व्यवस्था आसान नहीं होगी। कप्तानी, कोचिंग, चयन और खिलाड़ियों के कार्यभार का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। हर खिलाड़ी को यह भरोसा दिलाना होगा कि अलग टीम में होना उसकी अहमियत कम नहीं करता। दोनों टीमों में एक जैसी पेशेवर संस्कृति और तैयारी का स्तर बनाए रखना भारतीय क्रिकेट प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। फिर भी यह चुनौती भारत की बढ़ती क्रिकेट ताकत का प्रमाण होगी। एक समय था जब भारतीय टीम के बाहर कुछ ही खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के विकल्प माने जाते थे। आज तस्वीर बदल चुकी है। भारत के पास बल्लेबाजों, गेंदबाजों और ऑलराउंडरों की ऐसी लंबी कतार है, जो दुनिया की किसी भी मजबूत टीम को चुनौती दे सकती है। भारतीय क्रिकेट का अगला लक्ष्य इसलिए केवल अधिक मैच खेलना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो अगले दशक तक देश को लगातार सफलता दिला सके। 2028 का लॉस एंजिलिस ओलिंपिक इस अभियान का महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। अगर भारत अभी से अपनी प्रतिभाओं को सही दिशा, पर्याप्त अवसर और अंतरराष्ट्रीय अनुभव देता है, तो ओलिंपिक के साथ–साथ विश्व कप और अन्य बड़े टूर्नामेंटों में भी उसका दबदबा लंबे समय तक कायम रह सकता है। एक देश में एक मजबूत टीम होना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एक साथ दो विश्वस्तरीय टीमों के लिए पर्याप्त प्रतिभा होना क्रिकेट की असाधारण ताकत का संकेत होगा। भारतीय क्रिकेट जिस दिशा में बढ़ रहा है, उसमें आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि भारत के पास प्रतिभा है या नहीं, बल्कि यह होगा कि इतनी बड़ी प्रतिभा को कितनी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लॉस एंजिलिस 2028 की तैयारी इसी नई भारतीय क्रिकेट शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

(लेखक– कांतिलाल मांडोत)
(L 103 जलवन्त टाउनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड, नियर नन्दालय हवेली सूरत मो 99749 40324 वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार स्तम्भकार)

करोड़ों युवाओं के पास डिग्री है, हुनर नहीं

नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में शिक्षा एवं रोजगार को लेकर पांच बड़े सुधार की अनुशंसा की गई है। इनमें स्कूलों में कौशल शिक्षा का प्रशिक्षण, जिसमें आठवीं के बाद अनिवार्य रूप से स्कूल में प्रशिक्षण शुरू किया जाए। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं उनमें उद्योगों की भागीदारी भी हो। रोजगार और कौशल परिणाम का समय–समय पर आकलन सुनिश्चित किया जाए। काम के दौरान पढ़ाई और सीखने के अवसर बढ़ाने कैरियर मार्गदर्शन के विकल्प भी उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। नीति आयोग ने कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण मात्र देने की बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है, कि अभी 8 प्रतिशत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल ही प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। नीति आयोग का मानना है, कक्षा 6 से ही सभी स्कूलों में रोजगार, योग्यता और उद्यमिता कौशल की शिक्षा और प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। कक्षा 9 के बाद कौशल आधारित विषयों पर ध्यान देना होगा। डिग्री के साथ

रोजगार भी प्राप्त हो इस हेतु उच्च शिक्षा में परिवर्तन करने की जरूरत बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 फीसदी स्नातक डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। भारत में स्नातक प्रशिक्षित डिग्री धारी को अधिकतम औसत 29000 रुपए की नौकरी मिल रही है वहीं अप्रशिक्षित डिग्री धारी युवाओं को अधिकतम 22 हजार की नौकरी मिल रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है, कि शिक्षा का वर्गीकरण बहुत जरूरी है। शिक्षा को पांच वर्ग में जिसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगार की शिक्षा रोजगार प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षा व्यवस्था बनाना जरूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में 15 से 29 वर्ष के लगभग 8.7 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बताया गया है, जो घरेलू और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है, कि केवल 8.25 फीसदी स्नातकों को डिग्री के अनुरूप रोजगार मिला है। यह सबसे बड़ी विसंगति है।

नीति आयोग ने सरकारी आंकड़ों के अनुसार अपनी रिपोर्ट पेश की है। वास्तविक स्थिति इससे भयावह है। रोजगार को लेकर जो विभिन्न सर्वे हुए हैं, उसमें स्नातक बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में है। प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी करोड़ों लोगों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ है। डिग्री धारी किसी तरह से अपना खर्च निकालने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी और अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं। जहां पर डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। नीति आयोग ने भी मान लिया है डिग्री है लेकिन हुनर नहीं होने से देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। जिन लोगों ने डिग्री ले ली है जब उन्हे डिग्री के अनुरूप काम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में वह हताशा में चले जाते हैं। सर्वे के दौरान जो सबसे गंभीर बातें पता लगी हैं, उनमें पढ़े–लिखे युवाओं के पास नौकरी नहीं होने के कारण उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। कर्ज लेकर डिग्री प्राप्त करने वाले युवा सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनके ऊपर कर्ज चुकाने का दबाव है। लेकिन जब कोई नौकरी नहीं मिलती है तब ऐसी स्थिति में देश में आत्महत्या की संख्या भी युवाओं के बीच में बढ़ रही है। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह से सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में बड़ी तेजी के साथ बदलाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए चीन ने अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया है। आर्थिक आधार पर युवाओं को रोजगार मिले स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा और रोजगार में समन्वय बनाने का काम चीन कर रहा है। जिन क्षेत्रों में रोजगार मिल सकता है उसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुछ इसी तरह की व्यवस्था सरकार को भारत में करनी होगी। जिस तरह से तकनीकी, उपकरण और एआई इत्यादि का उपयोग बढ़ता जा रहा है, उसी के अनुसार शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों को बदलने की जरूरत है। डिग्री से रोजगार मिलेगा इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलने की जरूरत है। हुनर और जरूरत के अनुसार सेवा क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। सेवा क्षेत्र में आर्थिक संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। इस दिशा में नीति आयोग और भारत सरकार को ईमानदारी के साथ कार्य करने की जरूरत है।

लेखक– सनत जैन

जीवन से कीमती नहीं है मोबाइल

जरा सोचिए मोबाइल प्यारा है या जिंदगी? मलेरिया, डायरिया, पायरिया या डिफ्थीरिया या किसी और रोग की वजह से किसी की मृत्यु हो जाए तो बात समझ आती है, लेकिन यदि मोबाइल के लिए मोबाइलेरिया से कोई मौत को गले लगा ले तो क्या किया जा सकता है? धर्मशाला क्षेत्र के एक चौदह वर्षीय बच्चे ने इस आक्रोश में जान दे दी क्योंकि उसके अभिभावकों ने बच्चे के काफी देर मोबाइल पर गेम खेलने के पश्चात मोबाइल को अपने पास रख लिया।

मोबाइल के नशे में चूर अबोध बच्चे ने नाराजगी जताते हुए चुपचाप अपने कमरे में दुप्पट्टे से फांसी लगा ली। अपने अमूल्य जीवन की कोई कीमत न समझते हुए चौदह वर्षीय बच्चे का यह कदम बहुत ही दु:खद और पीड़ादायक है। 26 जुलाई 2026 को गगल थाना क्षेत्र में मोबाइल पाने के झगड़े में एक बारह वर्षीय बच्ची जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। रानीताल क्षेत्र में मोबाइल न मिलने पर एक अबोध बच्चा घर छोड़ कर चला जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आईफोन खरीदने जिद में पहाड़ी पर खड़े होकर बेटे को छलांग लगाते रोकने के असफल प्रयास में बाप और बेटे की मौत और बाद में मां के छलांग लगाने से एक ही परिवार के तीन सदस्य पल भर में प्राण खो बैठते हैं। मोबाइल के कारण आत्महत्या जैसे बहुत से मामले पुलिस के अभिलेखों में पंजीकृत हो रहे हैं। इस तरह की अनगिनत घटनाएं प्रतिदिन हमारे सामने आ रही हैं। इससे यह पता चलता है कि संचार और तकनीक की दुनिया ने हमें कितना मजबूर कर दिया है कि हम अपने अमूल्य जीवन की कीमत भी नहीं समझ पा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में न्यायालय द्वारा पत्नी द्वारा हर पल सोशल मीडिया पर व्यस्त रहने तथा पारिवारिक कर्तव्य न निभाने के लिए पीड़ित पति को तलाक दिलवाया जाता है। संचार क्रांति के युग में यह तो ठीक है कि मोबाइल हरेक व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मोबाइल के लिए जीवन की कुबार्नी देनी पड़े। बच्चे और अभिभावक कितने मजबूर हो चुके हैं कि बच्चा मोबाइल के बिना रह नहीं सकता और अभिभावक उसे रोक नहीं सकते। डाक्टरों, शोधकताओं और मनोविज्ञानियों का कहना है कि मोबाइल से न केवल व्यक्ति पर शारीरिक, सामाजिक असर पड़ रहा है बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी इसके दुष्प्रभाव का शिकार हुआ है। सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक से करोड़ों–अरबों कमाने वाले बड़े–बड़े कारोबारी भी अपने बच्चों को चौदह वर्ष तक मोबाइल से दूर रखते हैं। मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और स्नैप से जुड़े दिग्गज मालिक और अधिकारी बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करने के पक्ष में हैं। इस मोबाइल ने व्यक्ति की आंखों तथा स्मरण शक्ति को भी प्रभावित किया है। अस्पतालों में मनोवैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों के पास काउंसलिंग, परामर्श तथा निदान के बहुत से मामले आने शुरू हो गए हैं। यह हम सब जानते हैं कि मोबाइल के कारण व्यक्ति अपने तक ही सीमित हो गया है जिससे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक दूरियां भी बढ़ी हैं। घर में बैठे पति–पत्नी, बच्चों को अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त हुए आमतौर पर देखा जा सकता है। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से लोगों की आंखों में जलन, धुंधलापन, सिरदर्द, चक्कर आना, नींद न आना, गर्दन, कन्धे, पीठ में दर्द, मोटापा जैसी शारीरिक समस्याएं आम हो गई हैं।

आदमी की स्मरण शक्ति क्षीण हो रही है। बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, एकाग्रता की कमी, थकान, नहाना नहीं, भूख नहीं, चिंता, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, आक्रोश, आक्रामकता, किसी भी काम में मन न लगना, काम में टालमटोल करना, रील या सोशल मीडिया में व्यस्त रहना, बार–बार नोटिफिकेशन चैक करना जैसे लक्षण आम हो गए हैं। बच्चे परिवार के लोगों के साथ कम बातचीत करते हैं। हम परिवार के साथ रहते हुए भी मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। बच्चों में खेलने–कूदने और अन्य पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में कोई रुचि नहीं है। उनमें रचनात्मकता तथा सृजनात्मकता जैसी गतिविधियों का अभाव पाया जा रहा है। माता–पिता और अभिभावक अपने में व्यस्त हैं। उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं है। बच्चों की भावनाओं और संवेदनाओं को नहीं समझा जाता। बच्चे अकेलेपन में जी रहे हैं। निदा फाजली का शेह्रर याद आ रहा है, ह्यजिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबां मिली है मगर हमजुबां नहीं मिलता ह्ल बच्चों की सुनने वाला, उनकी किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक और मनोस्थिति को समझने वाला कोई नहीं। बचपन में अपनी जान छुड़ाने के लिए मां–बाप द्वारा बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाता है। मां–बाप और बच्चों के बीच में संवाद नहीं है। माता–पिता के दृष्टिकोण से आवश्यक यह है कि वे बच्चों के संवेगों, भावनाओं, संवेदनाओं, समस्याओं और उनकी मनोदशा को समझें। आमतौर पर बच्चों का जिद करना, आक्रोशित होना तथा आत्महत्या जैसे अंतिम विकल्प पर जाना इसी बात की परिणति है कि जीवन की आपाधापी और जीवन संघर्ष के बीच माता–पिता के पास अपनी संतानों के लिए समय ही नहीं है। उल्टी–सीधी और अश्लील साइट्स देखकर बच्चे अल्पायु में ही बाल्यावस्था से किशोरावस्था और युवावस्था में पहुंच रहे हैं। यहां पर संचार, तकनीक तथा मोबाइल प्रेमी ये अवश्य कहेंगे कि संचार और विकास क्रान्ति के इस युग में जहां दुनिया की आर्थिकी व सभी काम–धंधे मोबाइल, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से होते हैं, वहां पर कैसा संकीर्ण, दकियानूसी और पिछड़ा हुआ ज्ञान बांटा जा रहा है, परन्तु यह भी परम सत्य है कि जीवन बचेगा तभी सब कुछ संभव है। यदि आत्महत्याओं से सन्तानें ही नहीं बचेंगी या फिर वे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से स्वस्थ और सक्षम नहीं होंगे तो ऐसे अक्षम और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों का क्या करेंगे? आवश्यक यह है कि इन संचार संसाधनों का संतुलित प्रयोग हो। ये सभी संचार उपकरण हमारे जीवन को सुलभ बनाने के लिए हैं, न कि बर्बाद करने के लिए। घर–परिवार में अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। विशेष रूप से शिक्षण संस्थाओं के मुखिया और शिक्षकों से प्रार्थना है कि वे इस विषय पर बच्चों के साथ बड़ी गम्भीरता से चर्चा करें। देश और दुनिया चलाने के लिए मोबाइल और अन्य संचार उपकरण आवश्यक हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए नहीं। इस तरह मोबाइल का सीमित उपयोग सही है।

डा. सुरेश शर्मा, शिक्षाविद

आलेख

सही नहीं है यूपीआई पर कोई भी शुल्क

लोकसभा में 6 अगस्त 2026 को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन बिल पारित किया है, जिसके अनुसार अब यूपीआई एवं अन्य अधिसूचित इलैक्ट्रानिक भुगतानों पर बैंकों और अन्य पेमेंट प्रदात्ताओं पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाए जाने पर वैधानिक रोक समाप्त हो जाएगी। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं होगा और यूपीआई भुगतान देना और प्राप्त करना दोनों ही निशुल्क रहेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि यूपीआई के माध्यम से 2000 रुपए तक के भुगतान तो निःशुल्क रहेंगे ही, लेकिन 2000 रुपए से ऊपर के भुगतानों पर बैंकों और अन्य भुगतान प्रदात्ताओं पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकेगा, जो भुगतान प्राप्तकर्ता, यानी विक्रेता से वसूला जाएगा। हालांकि कितना शुल्क लगाया जाएगा, यह निश्चित नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, उनके अनुसार ऊंचे मूल्य के लेन-देन पर एमडीआर 0.25 से 0.5 प्रतिशत के बीच हो सकता है। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि छोटे विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई की सुविधा निशुल्क रहेगी।

क्या है सरकार का तर्क : सरकार द्वारा यूपीआई भुगतान के नियमों में इस बदलाव का जो कारण बताया जा रहा है, वो यह है कि अभी तक यूपीआई निशुल्क है, लेकिन इसकी लागत को किसी न किसी को तो वहन करना पड़ेगा। यूपीआई पर फीस लगाने के समर्थकों का कहना है कि बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) और पेमेंट कंपनियां सर्वरों पर ही नहीं, साइबर सुरक्षा और विस्तार पर भी खर्च करती हैं, जिसे किसी को तो वहन करना ही पड़ेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा कहते हैं कि यूपीआई को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाए रखने के लिए किसी को तो भुगतान करना ही पड़ेगा।

पब्लिक गुड है यूपीआई : अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल गैर प्रतिद्वंद्वी यानी ह्यनॉन-राइवलह्ल होता है, यानी किसी एक के इस्तेमाल से दूसरों के इस्तेमाल पर कोई बाधा नहीं आती, और ये बिना किसी रोक-टोक के सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, और किसी को इसके इस्तेमाल से रोका नहीं जा सकता। ऐसी सेवा को ह्यप्योर पब्लिक गुडह्ल यानी विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कहा जाता है। कभी-कभी, कुछ सेवाएं गैर प्रतिद्वंद्वी तो होती हैं, लेकिन उनमें लोगों को बाहर रखना मुमकिन होता है। ऐसी चीजों को पब्लिक गुड तो कहा जा सकता है, लेकिन ये ह्यप्योर पब्लिक गुडह्ल नहीं होतीं। प्योर पब्लिक गुड के उदाहरण हैं- कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, पार्क, स्ट्रीटलाइट और सडकें। यूपीआई पब्लिक गुड की दूसरी श्रेणी में आता है, जो प्रकृति से गैर प्रतिद्वंद्वी तो है, लेकिन कीमत वसूलने पर इससे अन्यों को वंचित किया जा सकता है (यानी कुछ लोगों को इससे बाहर रखा जा सकता है)। आम तौर पर, सार्वजनिक सेवाएं ऐसी होती हैं जो समाज के लिए फायदेमंद तो होती हैं, लेकिन उनमें निजी क्षेत्र का निवेश नहीं आता, भले ही सैद्धांतिक रूप से उन तक पहुंच को सीमित किया जा सकता हो। अगर सरकार ने यूपीआई को बनाया न किया होता, तो कोई भी निजी क्षेत्र की कंपनी इतना शानदार प्रोडक्ट नहीं बना पाती। सरकार पब्लिक गुड में इन्वेस्टमेंट करती है क्योंकि वे लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। यूपीआई भी ऐसा ही एक पब्लिक गुड है, जो प्रकृति में तो गैर प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन हां, इसमें वंचन मुमकिन है।

लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें इसके लिए फीस लेना शुरू कर देना चाहिए? ऐसे पब्लिक गुड पर फीस लेने का फैसला ह्यहानि-लाभ विश्लेषणह्ल के आधार पर किया जाना चाहिए। आम तौर पर, हमें यह समझना चाहिए कि अगर लागत की तुलना में फायदे बहुत ज्यादा हैं और लागत बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसे मुफ्त रखना ही सबसे अच्छा है। लंबे समय से भारत में लॉजिस्टिक लागत बहुत ऊंची रहती रही है, जिसके कारण हमारे उत्पाद दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे। लेकिन पिछले एक दशक से ज्यादा समय में लॉजिस्टिक लागत में कम से कम एक प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। एनसीएआर और डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार यह लॉजिस्टिक लागत 2014 में जीडीपी का लगभग 9 प्रतिशत होती थी, जो अब घटकर 8 प्रतिशत तक पहुंच गई है। लॉजिस्टिक लागत के घटने में यूपीआई का निशुल्क होना एक बड़ा कारण है। समझना होगा कि आज भारत में दुनिया के 49 प्रतिशत ऑनलाइन लेन-देन होते हैं, और जो निशुल्क हैं। यदि यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यह भी पब्लिक गुड की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार से सडकें, पार्क, स्ट्रीट लाइट, कानून व्यवस्था आदि जीवन को सुगम बनाती है, तो यूपीआई व्यवसाय को सुगम बनाती है। सरकार का दायित्व है कि व्यवसाय की सुगमता (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) सुनिश्चित करे। इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास भी कर रही है। यूपीआई इसमें काफी मदद कर रहा है। देश में सडकों के जाल, रेल सुविधा में बेहतरी और सरकार की नई योजनाएं, जैसे कॉरिडोर इत्यादि ने न केवल व्यवसाय को सुगम किया है, बल्कि उससे लॉजिस्टिक लागत में भी भारी कमी आ रही है।

कहीं सरकार अमरीका के दबाव में तो यह नहीं कर रही? : गौरतलब है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भारत में यूपीआई लेन-देन के निःशुल्क होने पर आपत्ति दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि शून्य एमडीआर नीति, रूपे कार्ड का प्रमोशन, रूपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक करने, डाटास्थानीयकरण नियम और एनपीसीआई द्वारा यूपीआई एप्लिकेशन कंपनियों पर 30 प्रतिशत बाजार भागीदारी की शर्त आदि अमरीकी कंपनियों के व्यवसाय के लिए बाधाएं डाल रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक अमरीका के दबाव में पारित किया गया है, क्योंकि यूपीआई ने अमरीकी कार्ड कंपनियों वीजा और मास्टर कार्ड के व्यावसायिक मॉडल को प्रभावित या यूं कहें कि ध्वस्त कर दिया है। ये कंपनियां विक्रेताओं से लेन-देन की राशि का 1 से 3 प्रतिशत वसूलती हैं, लेकिन अब विक्रेताओं को क्यूआर कोड के माध्यम से बिना किसी लागत के भुगतान मिल जाता है। यही नहीं एनपीसीआई द्वारा शुरू किए गए रूपे कार्ड से यह प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई। क्योंकि रूपे कार्ड और यूपीआई भुगतान पर कोई एमडीआर नहीं है। अब हर विक्रेता अंतरराष्ट्रीय कार्डों की बजाय यूपीआई से ही भुगतान लेना चाहता है। कुछ समय पूर्व रूपे क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से जोड़ देने के बाद इन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की चिंता और बढ़ गई है। गौरतलब है कि 2023 में रूपे क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी मात्र 3 प्रतिशत थी, जो अभी तक बढ़ते हुए 20 प्रतिशत हो चुका है, उनके द्वारा भुगतान तो 40 प्रतिशत तक पहुंच चुके हैं। इससे समझ में आता है कि अमरीका यूपीआई के निशुल्क होने से क्यों चिंतित है और वो क्यों चाहता है कि यूपीआई भुगतानों पर शुल्क लगाया जाए।

क्या सरकार को हो रहा है बहुत नुकसान : गौरतलब है कि यूपीआई इकोसिस्टम को चलाने में भारत सरकार वर्तमान में मात्र 2200 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। जहां तक बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं की बात करें तो उनके द्वारा साइबर सुरक्षा और विस्तार के लिए जो खर्च करना पड़ता है, वो तो उनका ही काम है। यूपीआई तो उन्हें आसानी से लेनदेन करने में सुविधा ही देती है। बल्कि यूपीआई के कारण बैंकों की लागत में खासी कमी हुई है और उनके लाभ लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ, बैंकों ने तो कभी एमडीआर लगाने की मांग भी नहीं की। बहरहाल, कहा जा सकता है कि यूपीआई पर फीस लगाने के कई नुकसान होंगे।

डा. अश्वनी महाजन
पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

संक्षिप्त वार्ता

विशेष सफाई अभियान से सफाई व्यवस्था को नई गति

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान का पूर्व महापौर एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रामनारायण दुबे ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सरकार और नगर निगम के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

रामनारायण दुबे ने कहा कि चिन्हित गंदगी वाले स्थानों पर विशेष अभियान के तहत सफाई और नियमित निगरानी से व्यवस्था में सुधार आएगा। दिल्ली जैसे महानगर में निरंतर सफाई अभियान के साथ नियमित निगरानी भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सड़कों, गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई के साथ नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी अभियान का उद्देश्य होना चाहिए। लोगों को कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने और घरेलू कचरा निगम कर्मचारियों को सौंपने में सहयोग करना चाहिए।

चीनी के बढ़ते दामों से बिगड़ा घर का बजट

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वेब वार्ता)। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर आजादपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता भारत सिंह राघव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीनी के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है।

भारत सिंह राघव ने कहा कि खुदरा बाजार में चीनी की कीमत पिछले महीने की तुलना में काफी बढ़ गई है। त्योहारों के मौसम में कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों की चिंता बढ़ी है और मिठाई सहित दैनिक जरूरत की वस्तुओं पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण करने में भाजपा सरकार विफल रही है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद अब चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि सीमित आय में गुजारा करने वाले परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत गंभीर चिंता का विषय है।

कुदसिया बाग में 101 पौधे रोपे

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली नगर निगम की ओर से कश्मीरी गेट स्थित ऐतिहासिक कुदसिया बाग में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान 101 पौधे रोपकर दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने का संदेश दिया गया। अभियान में दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त संजीव मित्तल, अतिरिक्त आयुक्त बी.एस. जगलान और जोनल उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने पौधे लगाए। उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और कुदसिया बाग में नियमित रूप से आने वाले लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

रोपे गए पौधों में आम, जामुन, अमरूद, इमली, आंवला, कटहल, अमलतास, कचनार, चंपा, गुलमोहर, हरसिंगार और नीम सहित फूलदार, फलदार एवं छायादार प्रजातियां शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार इन पौधों से बाग की हरियाली और जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जिम्मेदारी है।

पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले दीपक शर्मा

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वेब वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र से पूर्व सदस्य, केंद्रीय इस्पात एवं संचार मंत्रालय भारत सरकार दीपक शर्मा ने उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने कलराज मिश्र का कुशलक्षेम जाना और पटका व माला पहनाकर सम्मान किया। दीपक शर्मा ने कहा कि कलराज मिश्र ने उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न दायित्वों के साथ केंद्र सरकार में भी मंत्री के रूप में सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कलराज मिश्र अपनी ईमानदार और स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े पदों पर रहने के बावजूद कलराज मिश्र का व्यक्तित्व बेहद सरल, सहज और सौम्य है। दीपक शर्मा ने उनके अनुभवों और सार्वजनिक जीवन में योगदान की सराहना की।

उपराज्यपाल ने शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन में डी वॉल के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसी) के फेज 5 (ए) के तहत सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर पर शिवाजी मेट्रो स्टेडियम में नए भूमिगत मेट्रो स्टेशन की डी-वॉल (डायाफ्राम वॉल) के निर्माण कार्य शुभारंभ किया। उन्होंने इसे विकसित दिल्ली के लिए आधुनिक और निर्बाध कनेक्टिविटी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

उपराज्यपाल ने कहा कि आज शिवाजी स्टेडियम साइट पर काम शुरू होना दिल्ली मेट्रो के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मेट्रो के अस्तित्व में आने से पहले की दिल्ली को देखने के बाद इसके विस्तार ने वास्तव में शहर को बदल दिया है। हम इसके निरंतर प्रगति और विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग और समर्थन प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि आज सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के हिस्से के रूप में शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। शिवाजी स्टेडियम स्टेशन को फेज 5 (ए) के तहत मौजूदा मैजेंटा लाइन के जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम मार्ग तक विस्तार के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है।

24 जून को शुरू किया था निर्माण

सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर लगभग 9.913 किमी तक फैला है और इसमें नौ भूमिगत स्टेशन होंगे, जिसमें शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वार मेमोरियल-हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल है। सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के तहत शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर काम शुरू होना मध्य नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार में एक और मील का पत्थर है। इसी कॉरिडोर के तहत केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य 24 जून 2026 को शुरू किया गया था।

विज्ञप्ति के मुताबिक शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन एक भूमिगत स्टेशन होगा और एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज सुविधा के रूप में काम करेगा, जहां नए मैजेंटा लाइन स्टेशन को 230 मीटर लंबे भूमिगत सबवे के माध्यम से मौजूदा शिवाजी स्टेडियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन स्टेशन के साथ सहजता से एकीकृत किया जाएगा, जिससे दो मेट्रो कॉरिडोर के बीच सुविधाजनक इंटरचेंज संभव होगा। इसके अलावा शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से 800 मीटर लंबे भूमिगत सबवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसमें ट्रैवेलेटर लगे होंगे, जो दोनों स्टेशनों के बीच यात्रियों के लिए सहज और सुविधाजनक पैदल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नए शिवाजी स्टेडियम स्टेशन पर डायाफ्राम वॉल लगभग 38 मीटर की गहराई पर होगी, जो 12 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर होगी। इतनी गहराई पर निर्माण इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि स्टेशन मौजूदा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नीचे होगा। इसलिए, आगामी शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर निर्माण गतिविधियों में काम आगे बढ़ने के साथ निर्माण वाहनों की काफी आवाजाही होने की उम्मीद है। प्रति माह लगभग 3,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए प्रति माह लगभग 500 ट्रांजिट मिक्सर ट्रिप की आवश्यकता होगी, जबकि प्रति माह लगभग 15,000 क्यूबिक मीटर खुदाई के लिए प्रति माह लगभग 750 डंपर ट्रिप की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप खुदाई की गई सामग्री के निपटान के लिए प्रति दिन 25 डंपर ट्रिप का उपयोग होगा। शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों, स्कूली छात्रों, बंगला साहिब गुरुद्वारा आने वाले श्रद्धालुओं और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी लाभ होने की उम्मीद है। मेसर्स एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को यहां निर्माण कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, दूसरे दिन भी फ्लाइट्स प्रभावित

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, ट्रैफिक जाम लग गया और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स भी प्रभावित हुईं।

कुशक रोड, राजोकरी गांव, आईटीओ, कॉपरनिकस मार्ग, कनॉट प्लेस और राजाजी मार्ग समेत कई अहम इलाकों में जलभराव की खबर है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई और लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हुई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल, एम्स, अशोक रोड और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पानी भर गया। एम्स के पास फ्लाईओवर लूप पर तेज बारिश से काफी जलभराव हो गया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।

फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार को कम से कम 18 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं, जबकि 146 फ्लाइट्स लेट हुईं। खराब मौसम की वजह से यह परेशानी हुई। इससे एक दिन पहले सोमवार को भी भारी बारिश ने दिल्ली-एनसीआर को लगभग ठप कर दिया था। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के कई इलाकों में सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए थे, जिससे लोग घंटों जाम में फंसे रहे।

सोमवार को फ्लाइट ऑपरेशन पर भी बुरा असर पड़ा था। 26 फ्लाइट्स रद्द हुईं, 15 फ्लाइट्स को दूसरे शहरों में डायवर्ट किया गया और 390 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुईं। तेज बारिश ने दिल्ली में बारिश के आंकड़ों को सामान्य से ऊपर पहुंचा दिया है। 24 अगस्त तक सफदरजंग में 191.1 मिमी की जगह 246.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 29 फीसदी ज्यादा है। पालम में 227.2 मिमी बारिश हुई, जो 28 फीसदी ज्यादा है, जबकि लोदी रोड पर 233.2 मिमी बारिश हुई, जो 22 फीसदी ज्यादा है।

जाम की स्थिति न बने

सोमवार की भारी बारिश के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुग्राम में सभी कॉर्पोरेट ऑफिस, सरकारी विभागों और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को मंगलवार को वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई करने का निर्देश दिया। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि आगे की बारिश से लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो और शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने।

दिल्ली में मतदान केंद्रों की संख्या में 1914 की बढ़ोतरी, कुल संख्या 14,947 पहुंची

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वेब वार्ता)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के बाद संख्या 13,033 से बढ़कर 14,947 हो गई है। राजधानी में कुल 1914 मतदान केंद्रों की बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी सोमवार को दिल्ली चुनाव आयोग ने विज्ञप्ति जारी करते हुए दी। विज्ञप्ति के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रति मतदान केंद्र 1500 मतदाताओं की सीमा को घटाकर 1200 मतदाता प्रति मतदान केंद्र कर दिया है। इसके बाद युक्तिकरण की शुरूआत जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौजूदा मतदान केंद्रों के स्थानों के सत्यापन के साथ हुई। युक्तिकरण के दौरान आयोग के दिशा-निदेर्शों के अनुसार नए मतदान केंद्र स्थलों की पहचान की गई और नए मतदान केंद्र बनाए गए। जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी, वहां के मतदाताओं को सुविधा के लिए बगल के/ नव निर्मित मतदान केंद्रों पर स्थानांतरित भी किया गया। युक्तिकरण प्रक्रिया के दौरान सुझाव लेने के लिए सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विधानसभा स्तर पर और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं।

लापता होने के तीन दिन बाद जसोला नाले से किशोर का शव बरामद

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वेब वार्ता)। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जसोला गांव में पतंग पकड़ने की कोशिश के दौरान खुले नाले में गिरे 15 वर्षीय लड़के का शव घटना के तीन दिन बाद मंगलवार को बरामद कर लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

आठवीं कक्षा का छात्र मिथुन शनिवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे लापता हो गया था। उसके परिवार को संदेह था कि वह अपने घर के पास नाले में गिर गया है। लड़के की तलाश के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), बचाव दल और गोताखोरों ने खोज अभियान शुरू किया।

इससे पहले मिथुन के पिता का हाथ में छड़ी लेकर नाले में अपने बेटे को तलाशते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में दिख रहा था कि परेशान पिता खुद ही नाले में घुस रहे हैं। घटना के बाद, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कर्तव्य में कथित लापरवाही के लिए दक्षिण पूर्व (मध्य) क्षेत्र के एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की।

एडीबी से 2,500 करोड़ रुपये के ऋण से दिल्ली में जल आपूर्ति में सुधार किया जाएगा: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए 2,500 करोड़ रुपये के ऋण की मदद से शहर में बड़े पैमाने पर जल आपूर्ति सुधार शुरू करेगी।

गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में जल आपूर्ति को बेहतर करने के लिए दो भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि आपूर्ति के दौरान पानी के नुकसान को रोकने और वास्तविक समय की निगरानी के लिए बोर्ड द्वारा एक स्मार्ट मीटर परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

गुप्ता ने दिल्ली में जलभराव को अपनी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि डेढ़ साल पहले भाजपा के सत्ता में आने के बाद, शहर में जल आपूर्ति और सीवर नेटवर्क में सुधार के लिए जल मास्टर प्लान व ड्रेनेज मास्टर प्लान सहित कई कदम उठाए गए हैं।

आईआईटी दिल्ली में लगातार आत्महत्या की घटनाएं चिंताजनक, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए: केजरीवाल

नई दिल्ली,वेब वार्ता

आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के एम.एससी. विद्यार्थी ऋषिकेश की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच किए जाने की मांग की है।

केजरीवाल ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आईआईटी दिल्ली में ऋषिकेश की दुखद मौत से उन्हें बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच तय समय-सीमा के भीतर होनी चाहिए और छात्रों की सभी चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 65 से अधिक आईआईटी छात्रों ने आत्महत्या की है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। केजरीवाल ने कहा कि देश आईआईटी की शैक्षणिक उत्कृष्टता पर गर्व करता है, लेकिन उत्कृष्टता का पैमाना केवल रैंक, ग्रेड और प्लेसमेंट तक सीमित नहीं रह सकता।

केजरीवाल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक छात्र को जरूरत के समय मदद मिल सके। छात्रों की बात सुनने वाला कोई हो और मुश्किल परिस्थितियों में सहायता मांगने के लिए उन्हें सुरक्षित एवं भरोसेमंद माहौल मिले। उन्होंने कहा कि इस पूरे सिस्टम पर आत्म-मंथन करने और उसमें आवश्यक सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छात्रों को किसी भी स्थिति में निराश नहीं किया जा सकता।

सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 3 सितंबर को आएगा आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वेब वार्ता)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) घोटाले से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 3 सितंबर को इस पर अपना फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी मामला दर्ज होने के 27 महीने बाद की गई है। इस दौरान उन्हें सिर्फ एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था और जब दूसरी बार बुलाया गया तो गिरफ्तार कर लिया गया। वकील ने कहा कि मामले से जुड़ी सारी सामग्री दस्तावेजी है और सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही जांच एजेंसियों के कब्जे में हैं। ऐसे में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी और कार्यवाही दंडात्मक नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि दो साल बीत चुके हैं और जांच एजेंसी अब भी कह रही है कि जांच शुरूआती दौर में है और पूरा मामला ईडी की जांच पर निर्भर है। वकील ने अदालत में कहा कि सत्येंद्र जैन ने ये फैसले अकेले नहीं लिए थे। उन्हें तकनीकी ज्ञान रखने वाले अधिकारियों की सलाह और सिफारिशों पर निर्भर रहना पड़ा था।

रोहिणी एसटीपी की क्षमता को सत्येंद्र जैन के निर्देश पर 15-25 एमजीडी से बढ़ाकर 15-30 एमजीडी करने के आरोप पर वकील ने कहा कि रिकॉर्ड इस आरोप का समर्थन नहीं करते हैं। वहीं, एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने इसका विरोध किया। एसीबी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन आदतन अपराधी हैं और जमानत याचिका पर फैसला करते समय इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अकाली दल दिल्ली स्टेट के स्थापना दिवस पर उमड़ा संगत का सैलाब

नई दिल्ली, 25 अगस्त (वेब वार्ता)। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट का 5वां स्थापना दिवस मंगलवार को तालकटोरा स्टेडियम में बड़े उत्साह और धार्मिक माहौल के बीच मनाया गया। समारोह में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में संगत पहुंची, जिसके चलते पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया। पार्टी की सदस्यता को लेकर संगत में खासा उत्साह देखने को मिला।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका तथा कमेटी और पार्टी के महासचिव जगदीप सिंह काहलों के नेतृत्व में आयोजित समारोह में प्रमुख धार्मिक और सामाजिक हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, दमदमी टकसाल के प्रमुख ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, हरियाणा कमेटी से ज्ञानी बलजीत सिंह दादूवाल और भाई जसबीर सिंह रोडे सहित कई प्रमुख हस्तियां समारोह में पहुंचीं। समारोह में दिल्ली स्टेट अध्यक्ष एमपीएस चड्ढा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह केपी, शमशेर सिंह संधू, रविंदर सिंह खुराना, धर्म प्रचार विंग प्रमुख जसप्रीत सिंह करमसर सहित कमेटी के पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। हरमीत सिंह कालका और जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि पार्टी की स्थापना 2022 में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के 2021 के चुनावों के बाद पैदा हुई परिस्थितियों के बीच की गई थी। उन्होंने कहा कि संगत के फैसले को नजरअंदाज करने के प्रयासों के विरोध में दिल्ली की संगत और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों ने मिलकर पार्टी की स्थापना की थी।

उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता को लेकर दिल्ली की संगत में जिस तरह का उत्साह देखने को मिला, उसके लिए वे सदैव संगत के ऋणी रहेंगे। संगत के आशीर्वाद और सहयोग से स्थापना के समय किए गए वादों तथा पारित प्रस्तावों को ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि पंथ को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों से सिख समुदाय को बचाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित देश के किसी भी हिस्से में सिख समुदाय अथवा पंथ से संबंधित समस्या सामने आने पर उनकी टीम ने हमेशा आगे बढ़कर आवाज उठाई है।

हरमीत सिंह कालका और जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि पार्टी की स्थापना का उद्देश्य वही है, जिसके लिए वर्ष 1920 में उनके पूर्वजों ने कुर्बानियां देकर शिरोमणि अकाली दल की स्थापना की थी। उन्होंने दावा किया कि आज वे अकाली दल के वास्तविक सिद्धांतों और विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने दिल्ली में ऐसे लोगों को दोबारा गले लगाया, जो सिख कत्लेआम के आरोपियों सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और अन्य दोषियों को सम्मानित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय ऐसी गतिविधियों को स्वीकार नहीं कर सकता। नेताओं ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा बाला साहिब में निशुल्क डायलिसिस केंद्र, 50 रुपये में एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा, सस्ती दवाइयों के लिए बाला प्रीतम दवाखाना, कैंसर की जांच के लिए पीईटी स्कैन और मैमोग्राफी मशीन, एंडोस्कोपी सुविधा तथा गुरु हरिकृष्ण मेडिकल संस्थान में कैथ लैब जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं।

संक्षिप्त वार्ता

देवरिया में खनुआ नाले में एक किशोर की डूबने से मौत हुई

देवरिया 24 अगस्त। देवरिया जिले के बघौचघाट थाना क्षेत्र के मलवाबर बरनही गाँव में सोमवार सुबह दस बजे खनुआ नाले में स्नान करते समय एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह सूचना पुलिस ने दी है।

पुलिस के अनुसार देवरिया जिले के बघौचघाट थाना क्षेत्र के मलवाबर बरनही गांव के ही खनुआ नाले के घाट पर गांव के अंकित कुशवाहा (15) पुत्र प्रेमचंद्र कुशवाहा अपने साथियों के साथ नदी में स्नान करने लगे। और उसके साथी वीडियो बनाने लगे उसी बीच किशोर स्नान करने के दौरान ही वह गहरे पानी में चला गया। और डूबने लगा। यह देख उसके साथियों ने शोर किया तो गाँव के लोग आए और काफी प्रयास के बाद अंकित को नदी से बाहर निकाला। लोगों ने उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज देवरिया ले गये। जहां पर चिकित्सकों उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आयी पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज से कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में बघौचघाट थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि किशोर की मौत खनुआ नाले में स्नान करने से हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

यू पी आई ने भारत की डिजिटल शक्ति को वैश्विक पहचान दिलाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के 10 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान की व्यवस्था को सरल, सुरक्षित, त्वरित और पारदर्शी बनाकर सुशासन एवं वित्तीय समावेशन को नई गति प्रदान की है। यूपीआई ने डिजिटल लेन-देन को आम नागरिक के जीवन का सहज हिस्सा बनाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति ने बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को जन-जन की पहुंच तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज रेहड़ी-पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदारों, किसानों और श्रमिकों से लेकर छोटे-बड़े व्यापारियों तथा उद्यमियों तक, समाज के प्रत्येक वर्ग को यूपीआई के माध्यम से सुगम और त्वरित भुगतान की सुविधा मिल रही है। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है और आमजन के सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

7,968 करोड़ रुपये से बनेगा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे

वेब वार्ता, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने 7,968 .30 करोड़ रुपये की लागत से झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के विकास को मंजूरी प्रदान कर दी है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र, डिफेंस कॉरिडोर और जनपद झांसी के आसपास के महत्वपूर्ण स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रदेश एवं देश के अन्य क्षेत्रों से इन स्थानों तक सुरक्षित और द्रुतगति यातायात आवागमन की सुविधा मिलेगी। परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत 7,968 .30 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य के लिए होने वाला संभावित पूरा व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इस परियोजना में किसी प्रकार की वित्तीय भागीदारी अपेक्षित अथवा प्रस्तावित नहीं है।

महंगी चीनी के विरोध में सपा का अनोखा प्रदर्शन

प्याज की माला पहन शुरू किया पीडीए चीनी अभियान

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए अनोखा अभियान शुरू किया है। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव एवं हरदोई नगर पालिका अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी रामज्ञान गुप्ता ने महंगी चीनी के विरोध में पीडीए चीनी वितरण अभियान शुरू किया। नई बस्ती और गुप्ता कॉलोनी में उन्होंने करीब तीन कुंतल चीनी 20 रुपये प्रति किलो की दर से माताओं और बहनों को वितरित की।

रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि कुछ समय पहले भी उन्होंने 20 रुपये किलो की दर से चीनी वितरित कर महंगी चीनी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। चीनी जैसी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम बढ़ने से मध्यम और गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

अभियान के दौरान सपा नेता ने गले में प्याज की माला पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अंदाज में उन्हें गलियों में घूमते देख स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने कहा कि कभी गरीब की थाली का सामान्य हिस्सा रहा प्याज भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। सरकार को खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर तत्काल नियंत्रण करना चाहिए।

रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि पीडीए चीनी महंगाई के खिलाफ उनका सांकेतिक आंदोलन है। रक्षाबंधन तक अभियान जारी रहेगा। इस दौरान घर-घर और मोहल्लों में पहुंचकर माताओं एवं बहनों को 20 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य महंगाई के मुद्दे को आम जनता के बीच उठाना और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है। अभियान के दौरान सैकड़ों की संख्या में माताओं, बहनों और स्थानीय लोगों ने भी महंगाई को लेकर अपनी नाराजगी जताई। इस मौके पर गिरीश गुप्ता, धर्मेंद्र यादव दीपू, श्याम गुप्ता, शुभम गुप्ता, ठाकुर अंकित सिंह, सोनू गुप्ता परसपुर, रामदत्त गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, सोनू गुप्ता, प्रवेश गुप्ता, दुर्गेश यादव, चंद्रप्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

योगी सरकार की योजनाओं से आत्मनिर्भर बनीं उषा देवी, स्वयं सहायता समूह से मिली नई पहचान

लखनऊ/गोरखपुर, 25 अगस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (ठफछट) और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाएं आज स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। गोरखपुर के चरगांवा ब्लॉक के नाहरपुर गांव की रहने वाली उषा देवी की कहानी भी इसी बदलाव की प्रेरक मिसाल है, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव की सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गईं।

उषा देवी बताती हैं कि करीब चार वर्ष पहले उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर के खर्चों को पूरा करने में कठिनाई होती थी और आय का कोई स्थायी साधन नहीं था। इसी दौरान उन्हें पड़ोसी गांव की महिलाओं से स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी मिली। उन महिलाओं ने उषा देवी को समूह से जुड़ने और अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उषा देवी ने इस अवसर को अपने जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बनाया और स्वयं सहायता समूह से जुड़ गईं। समूह के माध्यम से उन्हें बचत, बैंकिंग और स्वरोजगार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलीं, जिसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया।

उषा देवी वर्तमान में समूह सखी के रूप में भी कार्य कर रही हैं। उनके नेतृत्व में कुल 9 स्वयं सहायता समूह संचालित हो रहे हैं. इनसे लगभग 130 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन समूहों से जुड़ी महिलाएं विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार कार्य कर रही हैं। कोई बकरी पालन कर रही है, कोई गाय पालन, कोई मुर्गी पालन, तो कोई सिलाई, कढ़ाई और छोटे व्यापार के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रही है। स्वयं सहायता समूहों ने गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें समाज में नई पहचान भी दिलाई है।

व्यवसाय को विस्तार दिया

उषा देवी बताती हैं कि जुलाई 2022 में उन्हें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लगभग 1.50 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। यह आर्थिक सहायता उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस राशि की मदद से उन्होंने अपनी किराने की दुकान को और मजबूत किया तथा व्यवसाय को विस्तार दिया। आज उनकी दुकान गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही है और परिवार के लिए नियमित आय का स्रोत बन चुकी है। उषा देवी पिछले चार वर्षों से अपनी दुकान का सफल संचालन कर रही हैं। उनकी मेहनत और लगन ने परिवार की आर्थिक स्थिति को पहले की तुलना में काफी बेहतर बना दिया है।

मजिस्ट्रेटी जांच के आश्वासन के बाद नवजात बच्ची के मौत के परिजन माने

कुशीनगर 25 अगस्त। कुशीनगर जिले में सात माह की नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 27 किमी पैदल मार्च किया। एडीएम और एएसपी के 72 घंटे में मजिस्ट्रेटी जांच के आश्वासन के बाद आक्रोशित परिजन शांत हुए।

कुशीनगर जिले में कप्तानगंज में सात माह में ही जन्म लेने वाली बच्ची की हुई मौत को लेकर आक्रोशित परिजन ग्रामीणों संग उपनगर के सच्चिदानंद अस्पताल के सामने सुबह आठ बजे से दस घंटे तक धरना दिया। उपचार में लापरवाही का आरोप लगा अस्पताल सील करने व चिकित्सक पर मुकदमा की मांग करने लगे। बात नहीं बनी तो पोस्टमार्टम के बाद सोमवार की शाम छह बजे शव के साथ पैदल ही जिला मुख्यालय रवींद्र नगर धूसके लिए चल दिए। चार घंटे में 27 किमी दूर तय कर रात लगभग दस बजे जिला मुख्यालय से मात्र पांच किमी पहले पडरौना के सुभाष चौक पहुंचे थे कि एडीएम वैभव मिश्र, एएसपी सिद्धार्थ वर्मा पहुंचे। यहीं पुलिस चौकी पर परिजन से वार्ता शुरू हुई। एक घंटे तक चली वार्ता के बाद एडीएम ने कहा कि 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेटी जांच होगी। दोषी होने पर अस्पताल के डाक्टर के विरुद्ध कार्रवाई होगी। तब परिजन माने।

बताते चले कि रामकोला थाना के अमडरिया गांव निवासी अश्वनी मिश्रा की 28 वर्षीय पत्नी मीनाक्षी देवी को 19 अगस्त को प्रसव के लिए सच्चिदानंद अस्पताल कप्तानगंज में भर्ती कराया था। 20 अगस्त को नार्मल बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसका उपचार चल रहा था। सोमवार सुबह मौत हो गई। इसके बाद परिजन चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिए। उनकी मांग थी कि, बच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रभारी थानाध्यक्ष कप्तानगंज विवेक पांडेय पुलिस टीम के साथ पहुंचे और डिप्टी सीएमओ आरडी कुशवाहा ने परिजन से बातचीत की। जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन परिजन नहीं माने। पूर्व विधायक सुभासपा नेता रामानंद बौद्ध व सपा नेता राजेश प्रताप राव बंटी भी समर्थन कुछ देर के लिए धरना में शामिल हुए।

शाम छह बजे पोस्टमार्टम के बाद नवजात का शव आया तो पैदल जिला मुख्यालय रवींद्र नगर धूस के चल दिए। रास्ते मे अधिकारियों ने वार्ता कर समझाने का प्रयास किए, लेकिन नहीं माने। पैदल ही 27 किमी दूरी तयकर पडरौना नगर के सुभाष चौक पहुंच गए। यहां एडीएम व एएसपी से एक घंटे तक वार्ता चली।

देवरिया में आपस में ही भिड़े भाजपाई, लाठी-डंडे चलने से मची अफरातफरी

देवरिया25 अगस्त। देवरिया जिले में मंगलवार को भाजपा के दो धड़ों में मारपीट हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि पीटीआई एजेंसी नहीं करती है। इस संबंध में कुछ भी बोलने से भाजपा के बड़े पदाधिकारी भी परहेज कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा के सोशल मीडिया राष्ट्रीय सहसंयोजक शिवानंद द्विवेदी के स्वागत में पार्टी के कार्यकर्ता जिले की सीमा खरोह के पास एकत्र हुए थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर दो धड़ों के बीच विवाद हो गया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे से गुत्थम-गुत्था हो रहे हैं।

निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करें : डीएम

वेब वार्ता, हरदोई

जिलाधिकारी अनुनय झा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। जनसुनवाई में कुल 83 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से जिलाधिकारी को अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और फरियादियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान कराया।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मयंक कुंडू सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

टड़ियावां में सीडीओ का औचक निरीक्षण, स्कूल व आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी ने मंगलवार को विकासखंड टड़ियावां के नानकगंज ग्रंट स्थित डिजिटल लाइब्रेरी, प्राथमिक विद्यालय कन्जड़पुरवा और आंगनबाड़ी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं में मिली कमियों पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।

डिजिटल लाइब्रेरी का रखरखाव संतोषजनक मिला। सीडीओ ने लाइब्रेरी की सभी सेल्फों व पुस्तकों की कोडिंग कराने, पाठकों के कार्ड बनवाने, वातानुकूलित व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

प्राथमिक विद्यालय कन्जड़पुरवा में 155 पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष केवल 70 बच्चे उपस्थित मिले। कई बच्चे बिना यूनिफॉर्म के थे। परिसर में घास-झाड़ियां, हैंडवॉश यूनिट में टोंटी का अभाव, शौचालय में प्रकाश व्यवस्था की कमी, फर्नीचर की कमी व खराब फर्नीचर तथा रसोईघर में साफ-सफाई का अभाव मिला। एमडीएम मेन्यू भी प्रदर्शित नहीं था। कक्षा चार के बच्चों से बोर्ड पर पढ़वाकर उनके शैक्षिक स्तर का आकलन किया गया।

लापरवाही पर प्रधानाध्यापक ममता तिवारी, ग्राम पंचायत सचिव विजय वर्मा तथा पर्यवेक्षकीय उत्तरदायित्व के लिए खंड शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार झा का अगस्त 2026 का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित करने के निर्देश दिए गए।

आंगनबाड़ी केंद्र में 39 पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष केवल 11 बच्चे उपस्थित मिले। वजन मशीन उपलब्ध नहीं थी और लंबाई मापने का यंत्र खराब था। केंद्र विद्यालय के बरामदे में संचालित मिला, जबकि विद्यालय में एक कक्ष खाली था। सीडीओ ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री उर्मिला यादव, मुख्य सेविका उमा गुप्ता और प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी संजू वर्मा को आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।

ईपीएफओ कार्यालय में बीएलएस प्रशिक्षण एवं रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन

वेब वार्ता, कानपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), आँचलिक कार्यलय व क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर में मंगलवार को बेसिक लाइफ सपोर्ट (बी एल इस) प्रशिक्षण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम के अंतर्गत बेसिक लाइफ सपोर्ट (बी एल एस) प्रशिक्षण सत्र का आयोजन पारस अस्पताल, कानपुर के सहयोग से किया गया, जिसमें डॉ. राहुल कुमार,

हेड, इमरजेंसी विभाग, पारस अस्पताल, कानपुर द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बी एल एस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ,बेसिक लाइफ सपोर्ट तथा अन्य जीवन रक्षक उपायों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन संकल्प सेवा समिति द्वारा किया गया। समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह चौहान की ओर से रक्तदान के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा अधिक से अधिक लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने का विशेष प्रयास किया गया। समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह चौहान ने स्वयं सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया और इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई। रक्तदान शिविर में 25 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिसमें ईपीएफओ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर उदय बक्सी, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (उत्तर प्रदेश), श्री शाहिद इकबाल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-क, कुमार अभिषेक क्षेत्रीय आयुक्त -'', प्रतीश सिंह क्षेत्रीय आयुक्त -'' एवं लेखाधिकारी राहुल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

महिला जनसुनवाई में राज्य महिला आयोग सदस्य ने सुनीं 28 शिकायतें

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई।आज राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश की सदस्य एकता सिंह ने निरीक्षण भवन, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में महिला जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुईं। उन्होंने महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न सहित अन्य मामलों से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। थाने से संबंधित प्रकरणों में उन्होंने संबंधित थानों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते

हुए उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली।

उन्होंने महिलाओं के हित में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि पात्र एवं पीड़ित महिलाओं को शासन की योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित कराया जाए। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम, सीओ सिटी, डिप्टी सीएमओ, वरिष्ठ सहायक सतीश कुमार, सेंटर मैनेजर शाहाबाद मिथिलेश कुमारी, सुरभि सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

8 मेगा औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने की मंजूरी

लखनऊ, 25 अगस्त। योगी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत आठ मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किए जाने की संस्तुति को मंजूरी प्रदान कर दी है।इन आठ औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदेश में कुल 2,901.97 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इन इकाइयों को नीति के तहत नेट एसजीएसटी और पूंजीगत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहनों का लाभ मिलेगा। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी) की 4 मई 2026 को हुई बैठक में इन औद्योगिक इकाइयों के प्रस्तावों पर विचार कर कैबिनेट से अनुमोदन की संस्तुति की गई थी। अब कैबिनेट ने इन इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए जाने की मंजूरी दे दी है।

नदियां उफनाईं, सड़कों पर बहने लगा बाढ़ का पानी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। हरिद्वार और नरौरा बांधों से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते सवायजपुर और बिलग्राम क्षेत्र में नदियों के तटवर्ती इलाकों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन खेतों में खड़ी हरे चारे समेत अन्य फसलों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। तटवर्ती क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर पानी बहने से आवागमन भी प्रभावित होने लगा है।

सवायजपुर तहसील क्षेत्र में गंगा, रामगंगा, गर्रा और गंभीर समेत करीब पांच नदियां बहती हैं। गंगा का बढ़ता जलस्तर रामगंगा में पहुंचने से तटवर्ती गांवों में पानी घुसने की आशंका बढ़ गई है। सांडी-श्रीमऊ मुख्य मार्ग पर श्रीमऊ के पास करीब एक फुट पानी बह रहा है। इससे वाहन चालकों के साथ स्कूली बच्चों को भी पानी से होकर

गुजरना पड़ रहा है। वहीं श्रीमऊ से कुसुमखोर मार्ग पर कडरिया जाने वाले संपर्क मार्ग पर भी पानी भर गया है।

बाढ़ के पानी से खेतों में खड़ी फसलों और हरे चारे के प्रभावित होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में पानी पहुंचने की स्थिति बन सकती है। संपर्क मार्गों पर पानी आने से ग्रामीणों को आवागमन में भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तहसीलदार विनोद कुमार और नायब तहसीलदार राजेश पटेल राजस्व टीम के साथ लगातार क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। तहसीलदार ने बताया कि बाढ़ राहत चौकियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को जलस्तर पर लगातार नजर रखने और किसी भी स्थिति की सूचना तत्काल प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से तटवर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

राम रहीम को 21 दिन की फरलो, 17वीं बार जेल से बाहर

सुनरिया जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा स्थित डेरा आश्रम के लिए रवाना

रोहतक। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई है। सुनरिया जिला कारागार प्रशासन ने उन्हें 21 दिनों की फरलो मंजूर की है। दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को यह 17वीं बार जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है।

जेल प्रशासन के अनुसार, राम रहीम को सुबह करीब 6.05 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनरिया जेल से बाहर निकाला गया, जिसके बाद वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम के लिए रवाना हो गए। इससे पहले वह मई में 30 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे।

2017 में मिली थी 20 साल की सजा

राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को सीबीआई की विशेष अदालत ने दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद 28 अगस्त 2017 को अदालत ने दोनों मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इस तरह उन्हें कुल 20 साल की कैद की सजा हुई।

सजा मिलने के बाद से अब तक राम रहीम कई बार पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर आ चुके हैं। मौजूदा अनुमति को मिलाकर यह उनका 17वां अवसर है, जब उन्हें अस्थायी रूप से जेल से बाहर रहने की मंजूरी मिली है।

चुनाव से पहले फरलो पर सियासी चर्चा तेज होने की संभावना

राम रहीम को फरलो ऐसे समय मिली है, जब पंजाब में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और चुनावी माहौल को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में उनकी रिहाई को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

गंभीर अपराधों में सजा काट रहे राम रहीम के बार-बार पैरोल या फरलो पर बाहर आने को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और आलोचना होती रही है। हालांकि, इस बार उन्हें जेल प्रशासन की ओर से 21 दिनों के लिए फरलो दी गई है और वह इस अवधि में सिरसा स्थित डेरा आश्रम में रहेंगे।

मराठी सीखो या लाइसेंस गंवाओ!

मुंबई। मुंबई में ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों ने सोमवार को सरकार के मराठी बोलने वाले नियम के विरोध में 3 दिन की हड़ताल बुलाई है। मराठी नहीं बोलने वाले ड्राइवरों का कहना है कि इससे उन पर ज्यादा बोझ पड़ेगा।

नियम के खिलाफ मुंबई में ऑटो-रिक्शा चालकों की 3 दिन की हड़ताल

प्रदर्शनकारी कांदिवली लिंक रोड पर विरोध किया। कई उम्रदराज ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और 55-60 साल की उम्र में नई भाषा सीखना मुश्किल है। बुधवार को ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस और बैज सस्पेंड किया जाएगा। राज्य में 20 अगस्त से उन ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। कई ड्राइवरों को नोटिस भी दिया गया है।

दीपके का दावा, सीजेआई का कॉकरोच वाला बयान सौरभ के लिए था

नई दिल्ली। एक राजनीतिक दल के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल उनके दल के प्रवक्ता सौरभ दास के लिए किया था। सौरभ दास भी इस बात से सहमत हैं। दीपके और दास दोनों का मानना है कि न्यायाधीशों और अदालती कामकाज पर लिखने, साथ ही सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन दाखिल करने के कारण ही यह टिप्पणी की गई थी।

एक साक्षात्कार में सौरभ दास ने अपने पत्रकारिता जीवन का उल्लेख करते हुए बताया कि वह अक्सर कानूनी मामलों और न्यायाधीशों पर लिखते रहे हैं। इसी दौरान, अभिजीत दीपके ने टिप्पणी की, जो कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया गया था, वह सौरभ के लिए किया गया था। यह मूल कॉकरोच है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा यही लिख रहा था। सौरभ दास ने दीपके की बात का समर्थन करते हुए कहा कि उस समय कई वकीलों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने उनसे संपर्क कर कहा था कि यह टिप्पणी उन्हीं के लिए की

गई है। दास ने बताया कि वह उस समय पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पर एक पत्रिका के लिए एक विस्तृत आलेख लिख रहे थे। उन्होंने एक अन्य न्यायाधीश पर भी इसी तरह का प्रोफाइल लिखा था और इसके लिए कुछ आरटीआई आवेदन भी दायर किए थे। इसी दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि ये युवा पेशे में नौकरी नहीं पाते, इसलिए मीडियाकर्मी बन जाते हैं, आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और सिस्टम पर हमला करते हैं। इस पर दास ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह संभव हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की इस टिप्पणी को शुरू में देश के बेरोजगार युवाओं के खिलाफ एक टिप्पणी के रूप में प्रचारित किया गया था। हालांकि, बाद में उन्होंने अदालत में स्पष्टीकरण दिया कि उनकी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा, मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से में सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत ढंग से पेश किया गया। मैंने उन लोगों की आलोचना की थी, जिन्होंने नकली और फर्जी डिग्रियों की मदद से वकालत जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं और इसलिए वे परजीवियों की तरह हैं और यह कहना बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की।

8वें वेतन आयोग के सामने रखा न्यूनतम वेतन में 300 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर 8वें वेतन आयोग के सामने न्यूनतम मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग रखी गई है। रक्षा कर्मचारियों के संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने मौजूदा 18 हजार रुपए के न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाकर 72 हजार रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। यदि यह मांग स्वीकार होती है तो न्यूनतम मूल वेतन में 54 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि फिलहाल 72 हजार रुपए केवल संगठन का प्रस्ताव है और इसे नया वेतन मानना जल्दबाजी होगी।

जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में जांच समिति के पुनर्गठन की मांग, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस पर कथित ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए गठित हाई लेवल कमेटी के पुनर्गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया, जिसके बाद अदालत ने आवेदन को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने याचिकाकताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायण ने आवेदन का जिक्र किया। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आवेदन पर आपत्ति जताते हुए इसे शरारतपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आवेदन में जांच समिति के पुनर्गठन के साथ कुछ मंत्रियों की जांच की मांग की गई है और न्यायाधीशों के नामों का भी उल्लेख किया गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत न्यायाधीशों के नामों का उल्लेख करना पसंद नहीं करती। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायण ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल आवेदन को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है और किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकताओं की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि हाई लेवल कमेटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समिति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध लोगों का चयन किया गया है और सभी पक्ष जांच में सहयोग करने के लिए मौजूद हैं। पीठ ने कहा कि मामले का अभी अंतिम निपटारा नहीं हुआ है और समिति को अपना काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया न्यायालय की निगरानी में आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समिति के पुनर्गठन की मांग वाले आवेदन को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

टीएमसी के बागी खेमे से लौटे अमदंगा विधायक कासिम सिद्दीकी

बोले- दीदी के साथ थे और रहेंगे, ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट से बनाई दूरी

कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच अमदंगा के विधायक कासिम सिद्दीकी ने बड़ा फैसला लिया है। कुछ महीने पहले बागी खेमे में शामिल हुए कासिम ने अब उस गुट से दूरी बनाते हुए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के साथ वापस जुड़ने की घोषणा की है।

कासिम सिद्दीकी ने कहा कि वह हमेशा से ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करते रहे हैं और आगे भी उन्हीं के साथ रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि बागी गुट में शामिल होने के दौरान उन्हें बताया गया था कि संबंधित समूह भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही काम करेगा। हालांकि, बाद में उन्हें महसूस हुआ कि गुट की गतिविधियों और दस्तावेजों में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के नेतृत्व का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जा रहा था।

कासिम सिद्दीकी ने बताया कि उनसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था और

उन्हें बताया गया था कि यह दस्तावेज ममता बनर्जी तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाद में जब उन्होंने दस्तावेज देखा तो उसमें ममता बनर्जी के नाम या उनके नेतृत्व का कोई उल्लेख नहीं था।

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने उन्हें राजनीतिक पहचान और चुनाव लड़ने का अवसर दिया। पार्टी ने उन्हें टिकट देकर विधानसभा पहुंचाया और उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व में जनता के बीच जाकर समर्थन मांगा। कासिम ने स्पष्ट कहा कि वह ममता बनर्जी के साथ हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में ही राजनीति करेंगे।

कासिम सिद्दीकी को पीरजादा के नाम से भी जाना जाता है और मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों में उनका प्रभाव माना जाता है। पिछले वर्ष तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें पार्टी में महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें अमदंगा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की।

कासिम सिद्दीकी की वापसी को तृणमूल कांग्रेस के अंदर जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके इस फैसले से पार्टी के बागी खेमे की गतिविधियों और आंतरिक समीकरणों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो सकती हैं।

शोपियां में दो जिंदा ग्रेनेड बरामद, तीन युवक गिरफ्तार

श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए शोपियां जिले में नाका चेकिंग के दौरान दो जिंदा हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने के संदेह वाले पांच पोस्टर बरामद किए हैं। इस मामले में मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षाबल नियमित नाका चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका गया, जिस पर तीन युवक सवार थे। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड और पांच संदिग्ध पोस्टर बरामद किए गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है और उसके रजिस्ट्रेशन व मालिकाना हक की जांच की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए तीनों युवकों की पहचान कुलगाम जिले के निवासियों के रूप में हुई है। उनकी पहचान जुनैद अहमद डार, आमिर यूसुफ और जुनैद मुजफ्फर के रूप में की गई है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बरामद पोस्टरों का इस्तेमाल इलाके में दहशत फैलाने और प्रतिबंधित आतंकी संगठन के प्रचार के लिए किया जा सकता था।

केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे और इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों के निर्यात पर लगी रोक को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब भारत से गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, साबुत गेहूं का आटा और अन्य संबंधित उत्पादों को विदेश भेजने की अनुमति मिल गई है।

सरकार ने सोमवार को गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों की निर्यात नीति में बदलाव किया। इसके तहत पहले लागू निर्यात प्रतिबंध को हटा दिया गया है। यानी अब इन उत्पादों का निर्यात सामान्य

रूप से किया जा सकेगा।

भारत ने 12 जुलाई 2022 को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी। इसका मुख्य कारण घरेलू बाजार में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतें थीं। उस समय रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण दुनियाभर में गेहूं की कीमतों में करीब 40 प्रतिशत तक तेजी आई थी। भारत से भी बड़ी मात्रा में गेहूं विदेश भेजा जा रहा था।

युद्ध के कारण ब्लैक सी क्षेत्र में गेहूं की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ा था। यह क्षेत्र दुनिया के करीब एक चौथाई गेहूं कारोबार से जुड़ा है। ऐसे में भारत ने वैश्विक बाजार में गेहूं की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, बाद में सरकार ने गेहूं के निर्यात में कुछ ढील दी थी और इस साल इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख टन सालाना तय की गई थी। अब नए फैसले के बाद गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों के निर्यात पर लगी पाबंदी पूरी तरह हटा दी गई है। 2022 के बाद पहली बार इन उत्पादों का निर्यात पूरी तरह से मुक्त किया गया है।

स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति वाली याचिका खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से यह साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक या कानूनी सामग्री पेश नहीं की गई कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है।

मामला प्रयागराज के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से जुड़ा है। छात्रा ने हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के बाद उसी स्कूल में कक्षा 11 में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। उसने अपनी मां के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्कूल प्रबंधन को निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति देने का निर्देश जारी करने की मांग की थी।

छात्रा ने बताया था धार्मिक परंपरा का हिस्सा

याचिका में छात्रा की ओर से तर्क दिया गया था कि हिजाब पहनना इस्लामी रीति-रिवाजों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी दावा

किया गया कि वह कक्षा 6 से ही स्कूल में हिजाब पहनती आ रही है। हालांकि, अदालत ने इस दावे और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद याचिका को स्वीकार नहीं किया।

अन्य छात्राएं हिजाब नहीं पहनतीं: कोर्ट

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने छात्रा से संबंधित विभिन्न कक्षाओं की तस्वीरों का अवलोकन किया। कोर्ट ने पाया कि स्कूल में याचिकाकर्ता के अलावा कोई अन्य छात्रा हिजाब नहीं पहनती है, जिसमें उसी धार्मिक समुदाय से जुड़ी छात्राएं भी शामिल हैं।

21 अगस्त को सुनाए गए फैसले में अदालत ने कहा कि सिर पर स्कार्फ पहनने को अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने के लिए याचिका में पर्याप्त आधार नहीं दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब किसी स्कूल का ड्रेस कोड निष्पक्ष और भेदभावरहित हो तथा उसे संस्थान में अनुशासन और समानता बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया हो, तो स्कूल प्रबंधन को अपने आंतरिक अनुशासन और निर्धारित यूनिफॉर्म को लागू करने की स्वतंत्रता है।

भारत की चिंता: पाकिस्तान के आसमान में मंडरा रहे तुर्की के विमान

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। उसने ड्रोन से लेकर और तमाम जरुरतें पाकिस्तान की पूरी की थी। आज इसी तुर्की

के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के आसमान पर मंडराते नजर आ रहे हैं। इससे भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि ये भी सही है कि भारत अपने आप में हर एक परिस्थिति से निपटने में समक्ष है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहराता सैन्य गठजोड़ एक बार फिर क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। पूर्व में भी भारत के खिलाफ कथित रूप से साझा रणनीतिक साठ-गांठ करने वाले इन दोनों देशों के बीच बीते कुछ दिनों से असामान्य सैन्य गतिविधि देखी जा रही है, जिसने चिंताएँ बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले 60 घंटों के दौरान पाकिस्तान के आसमान में तुर्की के कई सैन्य विमानों की लगातार और असामान्य आवाजाही दर्ज की गई है। विशेष रूप से, पाकिस्तान वायु सेना के दो प्रमुख एयरबेस पर तुर्की सैन्य विमानों को उतरते और उड़ान भरते देखा गया है, जो इस हलचल का केंद्र बने हुए हैं।

ताजा खबर

संक्षिप्त

छत्तीसगढ़ के राजेश दवे बने भारतीय महिला टी20 टीम के मैनेजर

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव एवं रणजी खिलाड़ी राजेश दवे को आगामी महिला टी20 एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पहले भी कर चुके हैं भारतीय महिला टीम के साथ काम

राजेश दवे इससे पहले भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। उनके अनुभव को देखते हुए एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारी दी गई है।

28 अगस्त से शुरू होगा महिला टी20 एशिया कप

महिला टी20 एशिया कप 2026 का आयोजन 28 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले से करेगी। 5 सितंबर को पाकिस्तान के साथ मुकाबलाइसके बाद भारतीय टीम 3 सितंबर को हांगकांग और 5 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले 10 और 11 सितंबर, जबकि फाइनल मुकाबला 13 सितंबर 2026 को खेला जाएगा।

पीएचई विभाग में 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति

रायपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 101 सिविल अभियंता और 10 विद्युत/यांत्रिक अभियंता शामिल हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा नियुक्ति के साथ ही सभी चयनित उप अभियंताओं की पदस्थापना के आदेश भी जारी किए गए हैं। चयनितों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118 पदों तथा उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 पदों पर भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा अप्रैल-2025 में लिखित परीक्षा ली गई थी। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जुलाई-2025 में विभाग द्वारा व्यापम की मेरिट सूची के अनुसार अभ्यार्थियों के दस्तावेज परीक्षण और पदस्थापना विकल्प के संबंध में कांउसलिंग के बाद उच्चतम न्यायालय में दायर स्थगन के कारण नियुक्ति प्रक्रिया विलंबित रही। उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 अगस्त 2026 को याचिका के निराकरण के बाद उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने तत्काल 22 अगस्त को प्रथम चरण में अनुशंसित चयन सूची के अनुसार सिविल के 101 उप अभियंताओं तथा विद्युत/यांत्रिकी के 10 उप अभियंताओं के पदस्थापना आदेश जारी कर दिए हैं।

बीज राखियों से सजेगा रक्षाबंधन, स्नेह के साथ मिलेगा हरियाली का संदेश

रायपुर। रायगढ़ जिले में इस बार रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के स्नेह के साथ पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का संदेश भी देगा। बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूह की महिलाएं धान, मक्का, बरबट्टी, लौकी, करेला, सेमी, कुम्हड़ा, भिंडी, उड़द, मसूर और मूंगफली सहित स्थानीय बीजों से आकर्षक बीज राखियां तैयार कर रही हैं। यह नवाचार महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय और स्वरोजगार का नया अवसर भी बन रहा है।

बीज राखी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जिले के सातों विकासखंडों में प्रतियोगिता आयोजित कर उत्कृष्ट राखियां तैयार करने वाली महिलाओं का चयन किया गया। चयनित महिलाओं ने जिला कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर श्री मयंक चतुवेर्दी सहित अधिकारियों को अपने हाथों से बनाई बीज राखियां पहनाईं। कलेक्टर ने महिलाओं को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया।

कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप स्व-सहायता समूह की महिलाओं को नवाचार, सशक्तिकरण और आजीविका से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय संसाधनों और हुनर से महिलाएं आय के नए साधन विकसित कर रही हैं। बीज राखियों की विशेषता यह है कि उपयोग के बाद इन्हें मिट्टी में दबाने पर इनमें मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधे का रूप ले सकते हैं। कम लागत, आकर्षक डिजाइन और पर्यावरण हितैषी स्वरूप के कारण इनकी मांग बढ़ रही है।

छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति के पाठ पढ़ेंगे 6वीं से 12वीं तक के बच्चे

100 कलाविद लेखक तैयार करेंगे 100 पाठ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्र कक्षा 6वीं से 12वीं तक स्थानीय कला, संस्कृति, परंपराओं और लोकजीवन से जुड़े विशेष पाठ पढ़ेंगे, जिससे नई पीढ़ी अपनी माटी और संस्कृति से गहरे से जुड़ सकेगी। छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला, संस्कृति, इतिहास, धरोहर, स्थापत्य, लोक परंपराओं, गीत-संगीत, संतों, महापुरुषों और रचनाकारों को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (स्ह्रश्वक्रञ्ज), शंकर नगर रायपुर में 24 से 26 अगस्त तक त्रि-दिवसीय आवासीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति पर केंद्रित आर्ट रिपोजिटरी तैयार करने के लिए प्रदेशभर के साहित्यकार, विषय-विशेषज्ञ, संस्कृतिविद, शोधकर्ता एवं जनसंचार विशेषज्ञ सहभागिता कर रहे हैं।

स्थानीय कला-संस्कृति को पाठ्य सामग्री से जोड़ने की पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ अपने संसाधनों से ऐसी पूरक पाठ्य एवं दृश्य सामग्री विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है, जिसके माध्यम से कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षक, प्रशिक्षक, शैक्षिक प्रबंधक एवं पालक समुदाय स्थानीय कला और सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकेंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी स्थानीय धरोहरों के प्रति कलात्मक बोध, संवेदना और गौरव की भावना विकसित करना है। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ की विविध कला एवं सांस्कृतिक विधाओं पर गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री तैयार करना है।

39 करोड़ रुपये खातों में ट्रांसफर

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना: सीएम साय ने श्रमिकों के मेधावी बच्चों का किया सम्मान

रायपुर। राजधानी रायपुर में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम में 200 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर 39 करोड़ रुपए श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारे तीन सौ बच्चे आज यहां उपस्थित है, जिनका चयन अटल उत्कृष्ट योजना में हुआ है उनको बधाई देते हैं। हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रमिक के बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं नहीं तो श्रमिक के बच्चे को अच्छे ड्रेस भी नहीं मिलते हैं।सीएम साय ने कहा, पिछले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था। उसी समय तय हुआ था कि आने वाले साल में बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे। 19-19 विद्यालय का छत्तीसगढ़ में चयन हुआ है। देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास। जब तक हमारे श्रमिकों का विकास नहीं होगा तब तक उनके बच्चों का विकास नहीं होगा। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। हमने यह अटल उत्कृष्ट योजना का शुभारंभ किया है। अच्छा अवसर हमारे बच्चों को मिला है इसका भरपूर लाभ लेने की आवश्यकता है। ज्योग्राफिकमैप्स और जीपीएस गाइड एक्सप्लोर करना सीएम ने कहा, स्टेज पर बच्चे आए थे उनसे हम पूछ रहे थे क्या बनना है? सभी बच्चों की कलेक्टर बनने की इच्छा है। इसके

लिए क्श्ष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप सभी लोगों के साथ आशीर्वाद है, आपकी मनोकामना पूरी हो। साय ने कहा, जन्म से लेकर मरने तक योजना है। सारे अधोसंरचना विकास हो रहा है वह श्रमिकों की बदौलत हो रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो मुझे भी काम करने का अवसर मिला। हमने PF के नंबर को यूनिवर्सल किए। इससे श्रमिक कहीं भी जाए तो उनका PF नंबर बदलता नहीं है। मिनिमम पेंशन को भी हमने 1000 रुपए किया। श्रमिकों के हर हित का ख्याल हम करेंगे।

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में 200 बच्चों का चयन

मुख्यमंत्री ने कहा, श्रम विभाग अलग अलग हितों में काम कर रहा है। प्रदेश के श्रमिकों के खातों में 39 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा की राशि उनके खातों में भेजे गए। आज श्रम विभाग द्वारा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत चयनित बच्चों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस योजना के तहत पिछले वर्ष 100 बच्चो का चयन हुआ था। इस वर्ष डबल 200 बच्चों का चयन किया गया है। इस तरह कुल 300 बच्चे और उनके अभिभावक आए थे। इस समारोह में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रामप्रताप भी उपस्थित रहे। दरअसल, ष्टरू साय मंगलवार को बालोद जिले के डौण्डीलोहारा स्थित लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित बिहान दीदी एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान 'बिहान दीदियों एवं विभिन्न स्व-सहायता समूहों की उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे। साथ ही महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त भी जारी करेंगे। इतना ही नहीं इस दौरान ष्टरू साय कुपोषण मुक्ति अभियान के अंतर्गत कुपोषित बच्चों के माताओं को सुपोषण किट के अलावा 'हर घर मुनगा' अभियान के तहत समारोह में उपस्थित महिलाओं को एक-एक मुनगा पेड़ का भी वितरण करेंगे।

महिलाओं को बड़ी सौगात: रक्षाबंधन से पहले आज जारी होगी महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त

छत्तीसगढ़ की महिलाओं को रक्षाबंधन त्योहार से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ष्टरू साय मंगलवार को राज्य के 68 लाख महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा: जेन जी युवाओं को भटकाने की कोशिश

रायपुर. छत्तीसगढ़ में नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में डोमिसाइल और अन्य डॉक्यूमेंट्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं. राजधानी में कांग्रेस स्टूडेंट विंग एनएसयूआई मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन करने वाली है. घड़ी चौक से एनएसयूआई कार्यकर्ता नीट छात्रों के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सरकारी आवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करेंगे. इस प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दिल्ली में बैठे कुछ आका साजिश कर जेन-जी युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. उनके दिमाग में दिमागी नक्सलवाद भरा हुआ है.

मूल निवासी प्रमाण-पत्र की होगी जांच: स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेडिकल प्रवेश में डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान मूल निवासी प्रमाण-पत्र और कैटेगरी/संवर्ग प्रमाण-पत्र की भी जांच की जाएगी, जिससे सीट का लाभ सिर्फ पात्र अभ्यर्थी को ही मिले. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इतिहास में पहली बार प्रदेश में एक साथ पांच मेडिकल कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं. इसके अलावा इस वर्ष 7 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 14 नर्सिंग कॉलेज और 10 मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि सरकार मेडिकल एडमिशन को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. पहली बार राजस्व विभाग की टीम भी एडमिशन प्रक्रिया में शामिल रहेगी. इससे प्रमाण पत्रों का गहन सत्यापन किया जाएगा जो भी गड़बड़ी करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. किसी भी तरह का लूपहोल नहीं छोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी एडमिशन प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है और घेराव की तैयारी की जा रही है. आखिर ये लोग युवाओं को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? कुछ भ्रमित लोग एडमिशन प्रक्रिया को विवादों में लाकर उसे जानबूझकर देर कराने का प्रयास कर रहे हैं.

दो दर्जन से अधिक आईपीएस के तबादले

रायपुर। सरकार ने 31 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। छह साल बाद पवन देव का प्रभार बदला गया है। उन्हें डीजी, नगरसेना एवं नागरिक सुरक्षा तथा अग्निशमन सेवाएं बनाया गया है। गुरजिंदर पाल सिंह को डीजी, प्रशिक्षण एवं महानिदेशक, राज्य पुलिस अकादमी की जिम्मेदारी दी गई है। एसआरपी कल्लूरी को एमडी, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाया गया है।

अब तक पवन देव कार्पोरेशन के प्रभार पर थे। इसी तरह 95 बैच के अफसर प्रदीप गुप्ता को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन एवं चयन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, अभियोजन की जिम्मेदारी दी गई है। विवेकानंद को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वित्त, योजना एवं प्रबंध, पुलिस मुख्यालय का दायित्व सौंपा गया है। दीपांशु काबरा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेलवे तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात बनाया गया है। खुफिया शाखा प्रमुख अमित कुमार को एडीजी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह डॉ. आनंद छाबड़ा को एडीजी, तकनीकी सेवाएं, डायल-112 एवं दूरसंचार बनाया गया है। ओपी पॉल को पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अंकित कुमार गर्ग को अतिरिक्त प्रभार संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर के साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं एसआईए का दायित्व दिया गया है।

इसके अलावा ध्रुव गुप्ता को आईजी (सीआईडी) के साथ सीसीटीएनएस/एससीआरबी तथा तकनीकी सेवाओं की जिम्मेदारी, बालाजी राव सोमावार को आईजी, अजाक, प्रशांत कुमार अग्रवाल को आईजी, एस4सी एवं तकनीकी सेवाएं और मिलना कुर्रे को आईजी, सीएएफ की जिम्मेदारी दी गई है। पारूल माथुर को डीआईजी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और मनीष शर्मा को डीआईजी, प्रशासन एवं चयन बनाया गया है। आदेश में अभिषेक मीणा को उप पुलिस महानिरीक्षक, सीएएफ, बस्तर, सदानंद कुमार को उप पुलिस महानिरीक्षक, सीएएफ, गिरिजाशंकर जायसवाल को उप पुलिस महानिरीक्षक, एस4सी एवं तकनीकी सेवाएं तथा एमएल कोटवानी को उप पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता की जिम्मेदारी दी गई है।

द्वितीय मुख्य परीक्षा में फेल और पास 10वीं-12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) द्वितीय मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 में शामिल विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। मंडल ने परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता के अनुसार स्कूलों में प्रवेश देने के निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए 27 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। इस संबंध में मंडल ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम 13 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। अब मंडल ने परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों के प्रवेश को लेकर सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं।

प्रमोशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कहा- वेतनवृद्धि रोकना मामूली सजा, पदोन्नति से नहीं कर सकते वंचित

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में पदोन्नति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि एक वेतनवृद्धि को बिना संचयी प्रभाव के रोकना मामूली दंड है. ऐसे दंड को बड़ा दंड मानकर कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार से बाहर नहीं किया जा सकता. न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता शेखर सिन्हा के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति के दावे पर विचार करने के निर्देश दिए. ज्योग्राफिकमैप्स और जीपीएस गाइड एक्सप्लोर करना याचिकाकर्ता शेखर सिन्हा वर्ष 1991 में आरक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और वर्ष 2008 में उन्हें प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति मिली थी. वर्ष 2021 में उनके खिलाफ एक वेतनवृद्धि को बिना संचयी प्रभाव के रोकने का दंड लगाया गया. इसके बाद जब उनके सहकर्मियों को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया, तो शेखर सिन्हा के नाम पर विचार नहीं किया गया. शेखर सिन्हा की ओर से अधिवक्ता अनादि शर्मा ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाया गया दंड गैर-संचयी प्रभाव वाला था. इसलिए इसे बड़ा दंड मानकर पदोन्नति के लिए विचार से बाहर करना कानूनन उचित नहीं है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा भरोसा किए गए 24 अप्रैल 2000 के परिपत्र और सुप्रीम कोर्ट के स्ह्ढ्ढद्ग श्द्ब स्र्ढ्ढस्रद्ब4ड्ड क्क्ष्ड्डस्रद्गह्यद्ध 1ह्य. ऋड्डस्रद्धद्बग्ड्ड क्क्ष्ड्डह्लड्डस्र छ्ठ्ठद्ग4 मामले में दिए गए फैसले के कानूनी पहलुओं को भी न्यायालय के समक्ष रखा.

गैर-संचयी प्रभाव वाली वेतनवृद्धि रोकना मामूली दंड

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले और मामले से जुड़े रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद स्पष्ट किया कि संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि रोकना बड़ा दंड है, जबकि बिना संचयी प्रभाव के वेतनवृद्धि रोकना मामूली दंड की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले में 24 अप्रैल 2000 के परिपत्र को लागू करना स्पष्ट रूप से गलत था और यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा राधिका प्रसाद दुबे मामले में निर्धारित कानून के विपरीत है. हाईकोर्ट ने शेखर सिन्हा की याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि उन्हें पदोन्नति दी जाती है तो पदोन्नत पद से जुड़े सभी लाभ उस तारीख से दिए जाएं, जिस तारीख को उनके कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति मिली थी.

पोस्टकार्ड पर लिखे भावुक संदेश राखी के साथ सैनिकों को मिला बच्चों का स्नेह और विश्वास

छात्राओं ने जवानों की कलाईयों पर बांधी राखी

रायपुर. रक्षाबंधन के मौके पर नवा रायपुर अटल नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राखी में भारतीय सेना के जवानों के सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भावनात्मक और प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया. छ्वह्रह्ल4 के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के अधिकारियों, जूनियर कमीशंड अधिकारियों और अन्य रैंक सहित कुल 72 सैन्यकर्मियों ने सहभागिता की.

बहनों ने बांधी राखी, जवानों को दिया सम्मान और विश्वास का संदेश

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने सैन्यकर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं. छात्राओं ने देश की सीमाओं की रक्षा में दिन-रात समर्पित जवानों के प्रति सम्मान, स्नेह और आभार व्यक्त किया. राखी के इस पवित्र धागे ने सैनिकों और विद्यार्थियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत किया.

नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर देश के रक्षकों के नाम लिखी भावनाएं

कार्यक्रम की विशेष पहल के रूप में विद्यार्थियों ने नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर भारतीय सेना के जवानों के लिए अपने हाथों से व्यक्तिगत पत्र और संदेश लिखे. इन संदेशों में विद्यार्थियों ने सैनिकों के साहस, त्याग और देशसेवा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उनके सुरक्षित रहने और देश की रक्षा में सदैव सफल होने की कामना की. बच्चों के इन भावपूर्ण संदेशों ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया.

जवानों ने साझा किए अनुभव, विद्यार्थियों को दिया देशसेवा का संदेश

इस अवसर पर सैन्यकर्मियों ने विद्यार्थियों से संवाद किया और भारतीय सेना के जीवन, अनुशासन और कार्यप्रणाली से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाने, जिम्मेदार नागरिक बनने और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया. संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों को सेना के जीवन को करीब से समझने और सैनिकों के समर्पण औचुनौतियों को जानने का अवसर मिला.

कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्टेशन मुख्यालय, रायपुर के प्रशासनिक कमांडेंट कर्नल अभिषेक उनियाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही. कार्यक्रम के समन्वय और संचालन में सूबेदार राज किशोर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. इस अवसर पर कर्नल अरिंदम मजूमदार, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण और विद्यार्थी उपस्थित रहे.

रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विद्यार्थियों ने अपने संदेशों और भावनाओं के माध्यम से देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और राष्ट्रभक्ति का भाव प्रकट किया. नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर लिखे बच्चों के संदेशों में देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के प्रति पूरे समाज की श्रद्धा और विश्वास की झलक दिखाई दी.

पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता पर भड़के छत्तीसगढ़ के शिक्षक संगठन

मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा जाएगा ज्ञापन

रायपुर

शिक्षा जगत में हलचल मची हुई है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रदेशभर के हजारों शिक्षकों ने मंगलवार को एक दिन का अवकाश ले लिया है, जिसके चलते कई ग्रामीण और शहरी स्कूलों में पठन-पाठन पूरी तरह से ठप हो गया है। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं और सरकार के खिलाफ आर-पार के मूड में नजर आ रहे हैं। इस पूरे विवाद की जड़ पदोन्नति के नियमों में %टेट% (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) की अनिवार्यता है। शिक्षक नेताओं का स्पष्ट तर्क है कि शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति नियमों में टेट की बाध्यता नहीं है। इसके अलावा, नियमानुसार शिक्षकों को टेट पास करने के लिए वर्ष 2028 तक का समय दिया गया है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति के लिए इसे अनिवार्य बनाकर शिक्षकों का लगातार मानसिक भयादोहन किया जा रहा है, जिसे शिक्षक किसी भी कीमत पर सहन करने को तैयार नहीं हैं। अपनी मांगों के समर्थन में मंगलवार शिक्षक तिरंगे के सम्मान के साथ सड़कों पर उतरकर भव्य रैलियां निकाल रहे हैं। मोर्चा के प्रमुख संयोजकों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि शिक्षकों की सुरक्षित सेवा और उनके अधिकारों की गारंटी उनके लिए सर्वोपरि है। प्रदेश के सभी जिलों में विशाल रैलियां निकालने के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि शासन प्रशासन तक शिक्षकों का आक्रोश पहुंच सके। शिक्षक नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार शिक्षकों के हित में सकारात्मक और व्यावहारिक फैसला नहीं लेती, तब तक यह संघर्ष अलग-अलग रणनीतियों के तहत जारी रहेगा। तर्क और तथ्यों के आधार पर शिक्षकों को उनका हक दिलाया जाएगा।

एशियाई खेलों में अपने पदकों का सूखा दूर करने उतरेगी मीराबाई चानू

नई दिल्ली। भारत की अनुभवी भारोत्तोलक मीराबाई चानू का लक्ष्य जापान के आइची-नागोया, जापान में होने वाले आगामी एशियाई खेलों में पदक जीतना है।

एशियाई खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेले जाएंगे और चानू को इसमें पांच सदस्यीय भारतीय भारोत्तोलन टीम में उन्हें शामिल किया गया है और वह इन खेलों मे पदक की प्रबल दावेदार के तौर पर उतरेंगी। चानू अब तक एक भी बार एशियाई खेलों में पदक नहीं जीत पायी हैं हालांकि उनक पास ओलंपिक पदक है।

गौरतलब है कि महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली चानू ने अपने करियर में ओलंपिक से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते हैं पर हैरानी की बात है कि वह एशियाई खेलों में एक भी पदक नहीं जीत पायी हैं। साल 2023 हांगझोऊ एशियाई खेलों में पदक के बेहद करीब थीं पर उन्हें अंत में चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। मीराबाई ने इस लक्ष्य के महत्व पर जोर देते हुए कहा है, एशियाई खेलों का पदक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे वहां जीतना है जहां मैंने पहले कभी पदक नहीं जीता है। इसलिए, एशियाई खेल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइची-नागोया में पदक जीतने से मीराबाई चानू का तीन बड़े खेल आयोजनों ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल में पदकों का संग्रह पूरा हो जाएगा, जो उन्हें इस खेल के दिग्गजों के क्लब में पहुंचा देगा। वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता 22 से 28 सितंबर तक टोकाई सिटिजन्स जिम्नेजियम में होगी, भारतीय टीम में चार महिलाएं और एक पुरुष भरोत्तोलक शामिल हैं। इस टीम की खासियत यह है कि पांच में से चार सदस्यों ने हाल ही में ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते थे, जो उनकी वर्तमान फॉर्म और क्षमता को दशार्ता है।

मीराबाई के अलावा, टीम में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव और 69 किलोग्राम वर्ग में हरजिंदर कौर शामिल हैं, दोनों ने पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। सेराम निरुपमा देवी 61 किलोग्राम कैटेगरी में महिला टीम को पूरा करती हैं। वहीं पुरुषों में, ऋषिकांत सिंह चनमबम एशियाई खेलों में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि होंगे। उन्होंने पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था और वे 60 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेंगे। इन सभी खिलाड़ियों का लक्ष्य अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के लिए गौरव अर्जित करना होगा।

सूर्यकुमार ने अब भी नहीं छोड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीदें

नेट्स में जमकर अभ्यास कर रहे

मुम्बई। टी20 विश्वकप में भारतीय क्रिकेट टीम को जीत दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव आजकल टीम से बाहर चल रहे हैं। सूर्यकुमार को विश्वकप के बाद कप्तानी हीं नहीं टीम से भी बाहर कर दिया गया था। इसका कारण उनका खराब फार्म और बढ़ती उम्र को बताया गया था सूर्या ने हालांकि अपनी वापसी की उम्मीदें अब भी नहीं छोड़ी हैं। सूर्या जानते हैं कि जिस प्रकार से टीम में लगातार नई प्रतिभाएं आ रही हैं उसमें उनकी वापसी आसान नहीं रहेगी। ऐसे में उनके पास कड़े अभ्यास और अपने को साबित करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। इसी कारण वह आजकल नेट्स में जमकर अभ्यास कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी साझा किया है। इसमें वह कड़ा अभ्यास करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा था अभ्यास को मैच से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाओ। जब आप नेट्स में खुद पर अधिक दबाव डालोगे, तो खेल के दौरान शांत रहना आपकी आदत बन जाएगी। मुश्किलों का सामना करो!

सूर्यकुमार के इस अभ्यास सत्र से यह साफ है कि उन्होंने टीम में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) साल 2026 के टी-20 विश्व कप को देखते हुए युवा प्रतिभाओं पर ही ध्यान दे रहा है। उसका प्रयास टीम को मजबूत बनाना है। इसको देखते हुए वह एक बार फिर सूर्यकुमार को अवसर देगा, ऐसे संभावनाएं नहीं हैं।

अब देखना यह होगा कि सूर्यकुमार का कठिन अभ्यास सफल होता है या नहीं। भारतीय टीम में वापसी का उनका सफर निश्चित रूप से आसान नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर अपनी अनूठी पहचान बनाने वाले इस खिलाड़ी ने हमेशा ही चुनौतियों का पूरे साहस से सामना किया है। अपने करियर में उन्हें बड़ी मुश्किल से ब्रेक तकरीबन 30 साल की उम्र में मिला था। इसे बाद करीब पांच साल तक वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते रहे हैं।

एसए टी-20 लीग के पांचवें सत्र में ईस्टर्न केप की ओर से खेलेंगे मिचेल मार्श

जोहांबर्ग। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट लीग एसए20 लीग का पांचवां सत्र सत्र क्रिकेट प्रेमियों के लिए विशेष रहेगा। इसमें कई बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते नजर आयेंगे। इस सत्र में ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिचेल मार्श से लेकर इंग्लैंड के ऑलराउंडर कुरेन खेलते दिखें। इन क्रिकेटरों के होने से लीग की लोकप्रियता और रोमांच का स्तर बढ़ेगा। मार्श तीन बार की चैम्पियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ जुड़कर एसए20 में अपनी नई पारी शुरू करेंगे। सनराइजर्स के पास पहले से ही क्विंटन डिकॉक, मैथ्यू ब्रीज्के, जॉर्डन हरमान और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स जैसे दमदार बल्लेबाज मौजूद हैं, जिससे उनकी बल्लेबाजी लाइनअप और मजबूत हो गई है। वहीं, इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम कुरेन अब मुंबई इंडियंस केपटाउन की जगह डरबन सुपर जाइंट्स के लिए खेलेंगे। वह अपनी राष्ट्रीय टीम के साथी जोस बटलर के साथ सुपर जाइंट्स टीम का हिस्सा होंगे, जो निश्चित रूप से टीम को एक नई गति प्रदान करेगा।

वहीं पिछले सत्र की उपविजेता प्रिटोरिया कैपिटल्स ने भी अपनी टीम में अहम बदलाव किए हैं। उन्हें शीर्ष क्रम में इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिल साल्ट और ऑस्ट्रेलिया के मैट शॉर्ट जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल गए हैं। कैपिटल्स के पास पहले से ही डेवाल्ड ब्रेविस, शेरफान रदरफोर्ड, आंद्रे रसेल और कोनोर ईस्टरहुइजेन जैसे आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं, जिससे उनकी बल्लेबाजी और भी जबरदस्त दिख रही है। वहीं इग्लैंड के एक और ऑलराउंडर विल जैक्स अब कैपिटल्स से एमआई केपटाउन टीम में शामिल हो गए हैं।

एसए20 लीग के कमिश्नर और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने इन बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मिचेल मार्श, सैम कुरेन और फिल साल्ट जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का लीग में शामिल होना इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है।

गौरतलब है कि एसए20 का अगला सत्र 17 जनवरी से शुरू होगा और क्रिकेट प्रशंसकों को लगभग एक महीने तक जोरदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। लीग का फाइनल मुकाबला 21 फरवरी को केपटाउन में खेला जाएगा, जहाँ विजेता टीम ट्रॉफी उठाएगी।

इंडिया ओपन 2028 का आयोजन दिल्ली की जगह गुवाहाटी में होगा : बीएआई

नई दिल्ली। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) ने कहा है कि प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूनार्मेंट इंडिया ओपन साल 2028 में नई दिल्ली की जगह पर गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। बीएआई के अनुसार आयोजन स्थाल में ये बदलाव सुरक्षा कारणों से किया गया है क्योंकि उस समय गणतंत्र दिवस होने के कारण सुरक्षा इंतजाम करना कठिन होगा। बीएआई ने ये भी कहा कि यह बदलाव केवल एक वर्ष के लिए है। वहीं साल 2027 का इंडिया ओपन दिल्ली में ही होगा, और 2028 के बाद, टूनार्मेंट 2029 में फिर से दिल्ली में वापस आ जाएगस।

दक्षिण अफ्रीकी टीम को झटका, ऑलराउंडर जेसन स्मिथ त्रिकोणीय सीरीज में नहीं खेलेंगे

जोहांसबर्ग। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को इसी माह 28 अगस्त से नामीबिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू होने जा रही त्रिकोणीय सीरीज में ऑलराउंडर जेसन स्मिथ के बिना ही उतरना होगा। स्मिथ चोटिल होने के कारण इस सीरीज से बाहर हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के अनुसार स्मिथ के जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आया है। सीएसए ने माना है कि इस ऑलराउंडर का नहीं खेलना टीम के लिए बड़ा झटका है। टीम प्रबंधन ने अभी तक स्मिथ के विकल्प की घोषणा नहीं की है। इससे साफ है कि उससे मौजूदा दल पर ही भरोसा जताया है।

सीएसए ने कहा, ऑलराउंडर जेसन स्मिथ दाहिनी जांघ की मांसपेशी खिंचाव के कारण विंडहोक में नामीबिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली ट्राई-सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्मिथ की चोट की गंभीरता का आकलन करने के लिए उनकी और जांच की जाएगी, विशेष रूप से नामीबिया के खिलाफ 09 सितंबर से शुरू होने वाली एकदिवसीय सीरीज में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

यह ट्राई-सीरीज 28 अगस्त से 6 सितंबर तक विंडहोक में खेली जाएगी, जिसमें बाएं हाथ के स्पिनर ब्योर्न फोर्टुइन अफ्रीकी टीम की कप्तानी करेंगे। इस ट्राई-सीरीज के

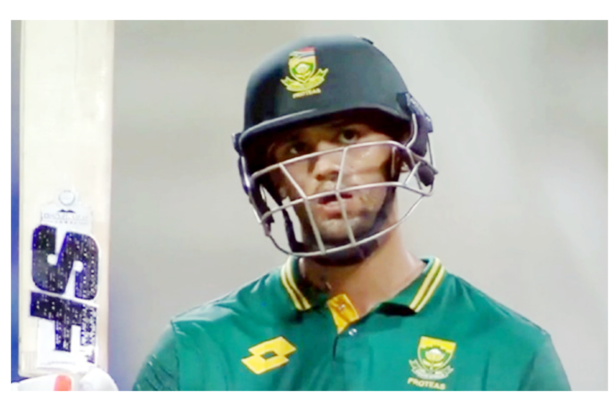

बाद, दक्षिण अफ्रीका 9 से 13 सितंबर तक नामीबिया के खिलाफ एकदिवीसीय मैच खेलेगा। यह प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका के लिए इस साल की शुरूआत में हुए पुरुष टी20 विश्व कप के बाद पहली ळ20कसीरीज होगी।

टीम में कई प्रमुख नियमित खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जिससे टीम युवा खिलाड़ियों से भरी है। इस बार ईथन बॉश, डुआन जानसेन जैसे उभरते हुए खिलाड़ियों को पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। इनके अलावा, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी और क्वेना मफाका जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी, जो पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं या अपनी घरेलू लीगों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, टीम के साथ नामीबिया का दौरा करेंगे। यह सीरीज इन खिलाड़ियों के लिए भी अपनी जगह पक्की करने और अनुभव हासिल करने का सुनहरा मौका है। टीम मंगलवार, 25 अगस्त को नाबीबिया रवाना होगी।

टीम इस प्रकार है :

ब्योर्न फोर्टुइन, ईथन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, कॉनर एस्टरहुइजेन, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, डुआन जानसेन, क्वेना मफाका, मोकोएना, न्काबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रेटोरियस, लुथो सिपाम्ला और प्रेनेलन सुब्रायेन।

कारोबार

रुपया चार पैसे टूटकर 95.74 प्रति डॉलर पर खुला

मुंबई। रुपया मंगलवार को शुरूआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चार पैसे टूटकर 95.74 पर आ गया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और आयातकों की ओर से डॉलर की बढ़ती मांग के कारण घरेलू मुद्रा पर दबाव है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि सरकारी बैंकों के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लगातार हस्तक्षेप से रुपये की गिरावट को अधिक बढ़ने से रोकने में मदद मिली। इससे एशियाई शेयर बाजारों में कमजोरी और ईरान को लेकर फिर बढ़ी भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद रुपया सीमित दायरे में रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.74 प्रति डॉलर पर खुला जो पिछले बंद भाव से चार पैसे की गिरावट है।

ईपीएफ खाते पर ब्याज कब तक? नौकरी छोड़ने पर तुरंत बंद नहीं होता, जानें पूरा नियम

नई दिल्ली। अक्सर कर्मचारियों को लगता है कि नौकरी छोड़ते ही उनके भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस आम गलतफहमी को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि ईपीएफ पर ब्याज कब तक मिलेगा, यह कर्मचारी की उम्र और रिटायरमेंट की स्थिति पर निर्भर करता है।

ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार, हर मामले में ब्याज

तुरंत नहीं रुकता, बल्कि कुछ खास प्रावधानों के तहत यह जारी रह सकता है। 55 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी मिलता है ब्याज ईपीएफओ के दिशानिदेर्शों के मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी 55 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ता है या स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेता है, तो उसके ईपीएफ खाते पर ब्याज तुरंत बंद नहीं होता। ऐसे मामलों में, कर्मचारी को 58 साल की उम्र तक खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस श्रेणी के लिए रिटायरमेंट की तारीख से तीन साल पूरे होने पर खाता निष्क्रिय मानकर ब्याज रोकने का नियम लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 50 या 52 साल की उम्र में नौकरी छोड़ता है, तो भी उसे 58 साल की आयु तक ईपीएफ जमा पर ब्याज मिलता रहेगा, भले ही नियोक्ता की ओर से नया अंशदान न हो।

55 साल या उससे अधिक उम्र में रिटायरमेंट पर अलग हैं नियमः यदि कोई कर्मचारी 55 साल या उससे अधिक की उम्र में रिटायर होता है, तो उसके ईपीएफ खाते पर ब्याज मिलने की अवधि अलग होती है। ऐसे मामलों में, रिटायरमेंट की तारीख से 36 महीने (तीन साल) पूरे होने के बाद ईपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है और उसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसे 61 साल की उम्र तक ब्याज मिलेगा। इसी तरह, 60 साल में रिटायर होने वाले कर्मचारी का खाता 63 साल की उम्र में निष्क्रिय होगा। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि खाते के निष्क्रिय होने का मतलब यह नहीं है कि उसमें जमा पैसा खत्म हो जाता है, बल्कि वैध दावे पर कर्मचारी को नियमों के तहत रकम का भुगतान किया जाता है।

नौकरी बदलने वाले और रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए सलाहः ईपीएफओ सलाह देता है कि नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को अपने पुराने ईपीएफ खाते की राशि को नए खाते में ट्रांसफर करा लेना चाहिए। वहीं जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, वे लागू नियमों के तहत अपनी ईपीएफ राशि निकाल सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और ईपीएफ रिकॉर्ड को हमेशा अपडेट रखें, ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके। यह जानना जरूरी है कि आपकी उम्र और रिटायरमेंट की स्थिति के हिसाब से ईपीएफ पर ब्याज कब तक मिलेगा, ताकि सही समय पर उचित वित्तीय निर्णय लिया जा सके।

एसबीआई का 2030 तक 200 लाख करोड़ का विशाल कारोबार का लक्ष्य

ग्राहकों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए होंगे दूरगामी फायदे

नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की तैयारी में है।

हालांकि कोई आधिकारिक लक्ष्य तय नहीं किया गया है, लेकिन बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने संकेत दिया है कि अगर मौजूदा वृद्धि दर जारी रही तो एसबीआई का कुल कारोबार साल 2030 तक 200 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यह वही साल होगा जब बैंक अपनी प्लेटिनम जुबली मनाएगा। जून 2026 के अंत में बैंक का कुल

बिजनेस 110.01 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें उसके कुल लोन और एडवांस शामिल हैं। चेयरमैन के अनुसार, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था 7 से 8 प्रतिशत की दर से बढ़ती है, तो एसबीआई की बैलेंस शीट में सालाना लगभग 11 से 12 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इस दर से बैंक का कारोबार लगभग हर छह साल में दोगुना हो सकता है। 2030 तक 200 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बैंक को लगातार मजबूत वृद्धि बनाए रखनी होगी। इस विस्तार का सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग सेवाओं में सुधार के तौर पर आम ग्राहकों को मिल सकता है। एसबीआई के विजन 2030 में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना एक प्रमुख लक्ष्य है। बैंक का बड़ा आकार टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश की संभावना पैदा करता है, जिससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। हालांकि, यह सीधे तौर पर सस्ता लोन या अधिक पैसा मिलने की गारंटी नहीं देता, बल्कि यह बैंक की समग्र दक्षता और नीतियों पर निर्भर करेगा। एसबीआई के आकार में वृद्धि का सीधा अर्थ है कि बैंक के पास देश के विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों को ऋण देने की क्षमता भी बढ़ेगी।

बैंक देश की लगभग एक चौथाई बचत जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पूंजी को कृषि, एमएसएमई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋण के रूप में लगाया जा सकता है, जिससे छोटे व्यवसायों को विस्तार के लिए धन मिलेगा, कंपनियां नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगी और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ेगा। यह अतिरिक्त निवेश रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे एसबीआई का बढ़ता कारोबार देश की आर्थिक वृद्धि के लिए एक शक्तिशाली क्रेडिट इंजन बन सकता है। बैंक अपनी वित्तीय मजबूती बनाए रखने पर भी केंद्रित है, जिसका लक्ष्य लगभग 12 फीसदी का सीईटी1 और 15 फीसदी का सीआरएआर बनाए रखना है, ताकि मुश्किल आर्थिक दौर में भी ऋण देने के लिए पर्याप्त पूंजी बनी रहे।

जापान से बढ़ता व्यापार घाटा चिंताजनक

नई दिल्ली। फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने मंगलवार को जापान के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारतीय निर्यातकों के लिए बेहतर बाजार पहुंच की मांग की। गोयनका ने टोक्यो में भारतीय प्रमाणन को अधिक मान्यता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों को जापानी बाजार में प्रवेश में कठिनाई हो रही है। फिक्की भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शीर्ष व्यापारिक संगठन है, इसका पूरा नाम 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' है।

गोयनका ने बताया कि भारत का जापान के साथ व्यापार मुख्य रूप से एकतरफा बढ़ा है। भारतीय फार्मा कंपनियों को जापान में अपने उत्पादों को पंजीकृत करने में विशेष दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने इसे एक बड़ी चुनौती बताया, जिसे हल करना आवश्यक है। फिक्की अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय उद्योग जापान में भारतीय प्रमाणन की मान्यता चाहता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन मुद्दों को भारत-जापान मुक्त व्यापार समझौते की व्यापक समीक्षा के बाहर भी सुलझाया जा सकता है। दोनों देशों के बीच दोतरफा वाणिज्य 2025-26 में 9.18 फीसदी बढ़कर 27.47 अरब रुपये हो गया। यह 2024-25 में 25.16 अरब रुपये था। 2025-26 में निर्यात 6.03 अरब रुपये और आयात 21.43 अरब रुपये रहा। गोयनका फ्ढऋग्रुप के उपाध्यक्ष भी हैं, जो 5.2 अरब रुपये का एक समूह है।

महत्वपूर्ण ख़बर

सामाजिक चेतना और जन-कल्याण को समर्पित रही कांवड़ यात्रा

- भोपाल। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के नेतृत्व में पंचवटी धाम, भेड़ाघाट से प्रारंभ हुई 121 किलोमीटर लंबी पांच दिवसीय भव्य कांवड़ यात्रा का प्रसिद्ध देव श्री जागेश्वर नाथ धाम, बांदकपुर पहुँचने पर अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ समापन हुआ। बांदकपुर धाम में राज्य मंत्री श्री लोधी, उनके अनुज श्री नीतेन्द्र सिंह तथा यात्रा के नेतृत्वकर्ता श्री सत्येंद्र सिंह ने स्वजनों एवं हजारों कांवड़ियों के साथ माँ नर्मदा के पवित्र जल से भगवान जागेश्वरनाथ का विधि-विधानपूर्वक जलाभिषेक कर लोक-कल्याण की प्रार्थना की।

विद्यार्थी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का भविष्य हैं

- भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज लखनऊ में "चुनावी साक्षरता क्लब (ईएलसी 2.0) और ईसीआईएनईटी" पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य युवा नागरिकों के बीच चुनावी साक्षरता और लोकतांत्रिक जागरूकता को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों और शिक्षकों सहित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, विद्यार्थियों को राष्ट्र का भविष्य बताते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनावी प्रक्रियाओं के ज्ञान और समझ को आगे बढ़ाने और लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए चुनावी परिषदें अनिवार्य हैं।

रक्षाबंधन पर ट्रेनों में भीड़ बढ़ी तो बसों ने बढ़ाया किराया...

भोपाल से पुणे-प्रयागराज समेत कई शहरों का सफर तीन से चार गुना महंगा

भोपाल। रक्षाबंधन के मौके पर भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग बसों का रुख कर रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती मांग के बीच ट्रैवल कंपनियों ने भोपाल से दूसरे शहरों के लिए बस किराया कई गुना बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के रूट पर किराया तीन से चार गुना तक बढ़ गया है।

अगस्त की शुरूआत में जिन रूटों पर किराया करीब 1000 से 1200 रुपये था, वहां अब यात्रियों को 4000 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। भोपाल से पुणे, मुंबई, प्रयागराज, अहमदाबाद, सागर, रीवा, उज्जैन और छिंदवाड़ा जाने वाली बसों में किराए की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

पुणे का किराया 5900 रुपये तक पहुंचा

सबसे ज्यादा असर भोपाल-पुणे, भोपाल-प्रयागराज, भोपाल-उज्जैन और भोपाल-सागर रूट पर दिखाई दे रहा है। सामान्य दिनों में पुणे का बस किराया करीब 1700 रुपये रहता है, लेकिन रक्षाबंधन के दौरान यह बढ़कर 5900 रुपये तक पहुंच गया है। प्रयागराज का किराया 1200 से बढ़कर 4000 रुपये तक हो गया है। सागर के लिए सामान्य किराया 350 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये और उज्जैन का किराया 350 से बढ़कर 1100 रुपये तक पहुंच गया है। अन्य रूटों पर भी किराए में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

वापसी में खाली सीटों का हवाला

ट्रैवल कंपनियों का कहना है कि त्योहार के दौरान भोपाल से दूसरे शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। मांग को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी लगाई जाती हैं। कंपनियों के अनुसार, यात्रियों को छोड़ने के बाद वापसी में पर्याप्त यात्री नहीं मिलते और कई सीटें खाली रहती हैं। इसी वजह से किराया बढ़ाया जाता है। हालांकि, आरटीओ जितेंद्र शर्मा ने कहा कि शासन ने बसों का किराया 2 रुपये प्रति किमी निर्धारित किया है। इससे अधिक किराया वसूले जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

अलग-अलग स्टैंड से मिलती हैं बसें

सागर, बीना, विदिशा, हलालपुर से संबंधित बसों के अलावा इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, इटारसी, बैतूल, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, देवास, सीहोर और रतलाम के लिए बसें उपलब्ध हैं। आईएसबीटी से मुलताई सहित लगभग सभी रूटों की बसें संचालित होती हैं।

जनशताब्दी में अतिरिक्त कोच

रक्षाबंधन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने रानी कमलापति-मदनमहल जनशताब्दी में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 12061 में 25 से 28 अगस्त और गाड़ी संख्या 12062 में 26 से 29 अगस्त 2026 तक एक-एक अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी कोच लगाया जाएगा। इससे सीटें बढ़ेंगी और प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है।

कुबरेश्वर धाम के लिए निकली कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु को हार्ट अटैक

भीड़ में एंबुलेंस अटकी, डॉक्टरों ने कंधे पर उठाकर पहुंचाया

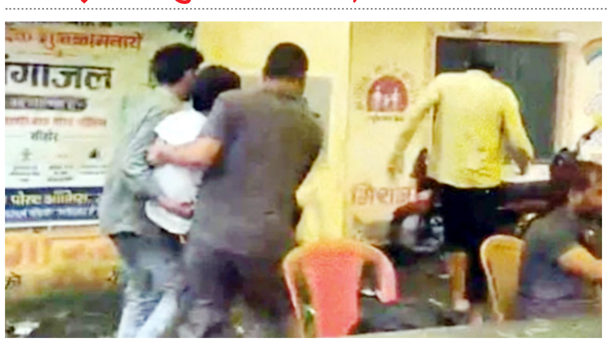

सीहोर। सीवन नदी तट से कुबरेश्वर धाम के लिए निकली भव्य कांवड़ यात्रा के दौरान मंगलवार को एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ गई। महाराष्ट्र के जलगांव से यात्रा में शामिल होने आए श्रद्धालु को मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर अचानक हार्ट अटैक आ गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

भीड़ के कारण नहीं पहुंच सकी एंबुलेंस

श्रद्धालुओं ने तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी। बताया गया कि एंबुलेंस हाईवे पर घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन कांवड़ यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ के कारण वह मरीज तक नहीं पहुंच सकी।

बिलासपुर तक चलाई जा सकती है इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव

इंदौर। इंदौर से बिलासपुर जाने वाले यात्री नर्मदा एक्सप्रेस से यात्रा कर पहुंचते हैं। यह ट्रेन लंबा रूट और ज्यादा समय में यात्रियों को बिलासपुर पहुंचाती है। लेकिन अब इंदौर-नागपुर वंदे भारत को बिलासपुर तक चलाने की तैयारी की जा रही है।

रेलवे बोर्ड को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है, अगर यह स्वीकार कर लिया गया तो इंदौर से यात्री एक दिन में ही बिलासपुर पहुंच सकेंगे। अभी तक वंदे भारत ट्रेन इंदौर से नागपुर के बीच चलती है। ऐसे में यात्री इससे नागपुर पहुंचकर बिलासपुर के लिए दूसरी ट्रेन से जाते हैं।

इंदौर और बिलासपुर के बीच अगर वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई तो यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे यात्री कम समय में ही एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच सकेंगे। लंबे समय से इन दो शहरों के बीच नई ट्रेन शुरू करने की मांग की जाती रही है।

एक दिन में होगी यात्रा

रेलवे बोर्ड को जो प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, उसके अनुसार इंदौर से वंदे भारत सुबह 6.10 पर रवाना होगी और दोपहर 2 बजे तक नागपुर पहुंचेगी। इसके बाद वहां से दुर्ग होते हुए शाम 7.25 तक बिलासपुर पहुंचेगी। वहीं बिलासपुर से इंदौर आने वाली वंदे भारत वहां से 6:45 पर रवाना होगी और नागपुर होते हुए रात साढ़े आठ बजे तक इंदौर पहुंचेगी।

मध्य प्रदेश में अंतर-राज्यीय साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़, 80 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन का पता चला, नरसिंहपुर के रहने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

छतरपुर। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक अंतर-राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह कथित तौर पर साइबर फ्रॉड से मिली रकम को ठिकाने लगाने के लिए 'म्यूल अकाउंट्स' (दूसरे लोगों के बैंक खातों) का इस्तेमाल करता था।

पुलिस ने कई राज्यों में लगभग 50 शिकायतों से जुड़े 80 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन का पता लगाया है। पुलिस के अनुसार, इन ट्रांजैक्शन से जुड़ी शिकायतें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में दर्ज की गई हैं।

ऑनलाइन रेटिंग बढ़ाकर पैसे दोगुना करने का झांसा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में आरोपियों के नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत भी मिले हैं। गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक व्यक्ति को एक ऐप के जरिए उसकी ऑनलाइन रेटिंग बढ़ाकर पैसे दोगुना करने का झांसा दिया और उससे 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। आरोपियों

ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम विज्ञापनों के जरिए लोगों से बैंक खाते किराए पर लिए, उनमें साइबर फ्रॉड से मिली रकम जमा की और तुरंत उस पैसे को दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने बताया कि जांच से यह भी पता चला है कि पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदला जा रहा था।

पुलिस ने बताया कि अब तक संदिग्ध बैंक खातों में साइबर अपराध से जुड़े लगभग 80 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन का पता चला है। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि मोहित चौबे नाम के एक व्यक्ति ने हाल ही में खजुराहो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि टेलीग्राम ऐप के जरिए उसकी ऑनलाइन रेटिंग बढ़ाकर पैसे दोगुना करने का झांसा देकर उसके साथ लगभग 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई।

मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई

मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए तकनीकी सबूतों, बैंक खातों, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बातचीत के तरीकों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि जांच में नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव इलाके में सक्रिय एक गिरोह की संलिप्तता का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से जुड़े बैंक खातों में 1.5 लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं और उनके पास से कई एटीएम कार्ड, बैंक खाते खोलने में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन और 38,000 रुपये नकद जब्त किए हैं। साकलेचा ने बताया कि आरोपियों की पहचान शुभम उर्फ शिवम पटेल, नीरज पटेल, कैलाश उर्फ केवल रजक और हीरालाल उर्फ संदीप रजक के तौर पर हुई है। ये सभी नरसिंहपुर के गोटेगांव के रहने वाले हैं। आगे की जांच चल रही थी और गैंग में शामिल अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही थी।

आबकारी विभाग की कार्रवाई से खुलासा

ग्वालियर। शराब के ठेकों पर ही शराब नहीं अब कॉलोनियों व मोहल्लों पर भी गुपचुप बिक रही है। इससे यह भी स्पष्ट है कि अवैध शराब का नेटवर्क शहर में फैला हुआ है। एक किराने की दुकान पर वह सब मिल रहा है जो शराब के ठेके पर मिलता है। सोमवार को आबकारी विभाग की कार्रवाई में इसका खुलासा भी हुआ है।

अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रह तथा परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मुखबिर से प्राप्त सुचना के आधार पर वृत्त आंतरिक क्षेत्र में घाटीगांव-मोहना क्षेत्र में, वृत्त डबरा के पिछोर क्षेत्र में तथा ग्वालियर शहर में अबैध मदिरा की सूचना पर मय आबकारी बल के दबिश दी।

दुकान से देशी और अंग्रेजी शराब बरामद

ग्वालियर शहर के महावीर नगर क्षेत्र से शैलेन्द्र सिंह बघेल की दुकान से 107 पाव देशी मदिरा प्लेन, 15 पाव देशी मदिरा मसाला, आईकोनिक वाइट के 22 अद्दी, ओल्डमॉक के दो अद्दी, ऐट पीएम के 12 अद्दी तथा बोल्ट बियर की 44 कैन, कुल मात्रा 57.46 लीटर देशी एवं अंग्रेजी मदिरा बरामद की गयी।

2500 किलो गुड़ लहान बरामद

मोहना कंजर डेरा से 5 प्लास्टिक की टांकियों में कुल 2500 किलो गुड़ लहान बरामद हुआ। डबरा के पिछोर क्षेत्र में गुंहार एवं एकारा उसर डेरा पर जमीन पर बने गड्ढों से लगभग 2200 किलो गुड़ लहान बरामद हुआ। कुल चार केस दर्ज किए, आरोपी शैलेन्द्र सिंह बघेल पुत्र नरोत्तम बघेल के विरुद्ध धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत केस बनाया।

वन स्टॉप सेंटर की संवेदनशील काउंसलिंग से फिर जुड़ा बिखरता परिवार

भोपाल। समय पर हस्तक्षेप, संवेदनशील काउंसलिंग और सकारात्मक मध्यस्थता किसी टूटते परिवार को फिर से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रीवा में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित वन स्टॉप सेंटर ने ऐसे ही एक प्रकरण में प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए लंबे समय से तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन से गुजर रहे दंपती के बीच संवाद स्थापित कराया। केंद्र के निरंतर प्रयासों के बाद पति-पत्नी ने अपने मतभेद दूर कर पुनः साथ रहने और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया।

मामला मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के ग्राम महरी निवासी रंजना साहू और उनके पति सुनील साहू से संबंधित है। दोनों का विवाह 13 दिसंबर 2021 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुआ था। विवाह के शुरूआती महीनों में पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में आवेदिका ने ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए वाहन की मांग तथा पति द्वारा नशे की स्थिति में मारपीट और मानसिक प्रताड़ना किए जाने की शिकायत वन स्टॉप सेंटर, रीवा में दर्ज कराई। लगातार बढ़ते विवादों के कारण दंपती का वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर पहुंच गया था।

शिकायत प्राप्त होने के बाद वन स्टॉप सेंटर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों से संपर्क किया और काउंसलिंग के लिए बुलाया। प्रारंभिक निर्धारित तिथि 9 जून को अनावेदक के उपस्थित नहीं होने के बावजूद केंद्र ने प्रयास जारी रखे। लगातार संपर्क और फॉलोअप के बाद 16 जून को पति सुनील साहू केंद्र में उपस्थित हुए। इसके बाद दोनों पक्षों की समस्याओं को समझते हुए संवेदनशीलता के साथ काउंसलिंग और मध्यस्थता की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। वन स्टॉप सेंटर रीवा की प्रभारी प्रशासक सुश्री श्रुति मिश्रा, परामर्शदाता सुश्री सलमा खान, प्रधान आरक्षक सुश्री रंजना तिवारी तथा केस वर्करों ने दोनों पक्षों से संवाद कर उन्हें वैवाहिक जीवन में आपसी सम्मान, विश्वास और संवाद के महत्व को समझाया। काउंसलिंग के दौरान पति को नशे और हिंसात्मक व्यवहार के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की मारपीट अथवा मानसिक प्रताड़ना नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 26 अगस्त को मालनपुर में गॉदरेज की चौथी विनिर्माण इकाई का करेंगे शुभारंभ

450 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 2250 से अधिक रोजगार सृजित होंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 26 अगस्त को भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गॉदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की विस्तारित चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे।

इकाई के विस्तार पर 450 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। इससे मालनपुर में उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ 2,250 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव पीडब्ल्यूडी नियुक्तियों के प्रमाण-पत्र भी वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा भिंड जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गॉदरेज समूह के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

विस्तार के अंतर्गत 10 मीट्रिक टन प्रति घंटे क्षमता वाला निरंतर सैपोनिफिकेशन संयंत्र और प्रति मिनट 217 बंडल की क्षमता वाली स्वचालित पैकेजिंग प्रणाली स्थापित की जा रही है। इसके साथ प्रतिवर्ष 42 करोड़ हेयर कलर सैशे, 14 करोड़ मच्छर निरोधक उत्पाद और 10 करोड़ एयर फ्रेशनर सैशे के उत्पादन की क्षमता विकसित होगी। हेयर क्रीम उत्पादन की क्षमता 7,300 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। इससे भिंड और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। विस्तार के बाद राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 185 करोड़ रुपये का अतिरिक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

गॉदरेज द्वारा उत्पादन विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉव जोंस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार गॉदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दुनिया की दूसरी सबसे टिकाऊ एफएमसीजी कंपनियों में शामिल है। मालनपुर संयंत्र में शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन प्रणाली के साथ 204 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

गॉदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्ष 1991 से मालनपुर में संचालित है। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कंपनी का संयंत्र 65 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहां अब तक 850 करोड़ रुपये का संचयी निवेश किया जा चुका है। तीन दशक से अधिक समय में यह संयंत्र गॉदरेज के विनिर्माण तंत्र के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। यहां साबुन, हेयर कलर और घरेलू कीटनाशक सहित विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है।

नई चौथी विनिर्माण इकाई के विस्तार से मालनपुर संयंत्र की उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। वर्तमान में यहां प्रतिवर्ष 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन साबुन नूडल्स और 70 हजार मीट्रिक टन तैयार टॉयलेट साबुन के उत्पादन की क्षमता है। विस्तार के बाद साबुन नूडल्स की क्षमता बढ़कर 2 लाख मीट्रिक टन तथा तैयार साबुन की क्षमता 1 लाख 20 हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। इस प्रकार कुल उत्पादन क्षमता 3 लाख 20 हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। इससे मालनपुर संयंत्र एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत साबुन विनिर्माण इकाई बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

एसएफआईसी डेटा एनालिटिक्स के आधार पर की कड़ी कार्रवाई

भोपाल। राज्य में शासकीय निधियों के संरक्षण और वित्तीय पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की जा रही निगरानी के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेस सेल (एसएफआईसी) द्वारा डेटा एनालिटिक्स के आधार पर किए गए गहन विश्लेषण के बाद 530 से अधिक आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा चुकी है। गंभीर मामलों में संलिप्त 22 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस सख्त निगरानी और समानांतर जांच प्रणाली से अब तक गबन एवं अनियमित ट्रांसफर की कुल 223 करोड़ रुपए की राशि शासन की संचित निधि में सफलतापूर्वक वापस कराई जा चुकी है। एसएफआईसी द्वारा वर्ष 2011 से अब तक के वित्तीय लेनदेन का नियमित डेटा विश्लेषण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में कुल 315 करोड़ रुपए की राशि को 'संदिग्ध श्रेणी' में चिन्हित कर जांच के अधीन रखा गया है।

भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की रिपोर्ट नहीं होगी सार्वजनिक, एमपी हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इंदौर। भागीरथपुरा में गत दिसंबर-जनवरी माह में दूषित पानी पीने से हुई 36 मौतों के मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की रिपोर्ट के सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। इसकी प्रति वकीलों को भी नही मिलेगी। कोर्ट ने कहा सिर्फ वो ही वकील रिपोर्ट देख सकेंगे जिनका वकालतनामा मामले में पेश है। कोर्ट ने वकीलों को भी इस बात की हिदायत दी है कि रिपोर्ट को लेकर मीडिया में चर्चा न करें।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। आयोग ने अपनी जांच पूरी कर हाल ही में 500 पेज से अधिक की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के हर पहलू की बारीकी से जांच की है। रिपोर्ट में तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों के साथ ही स्थानीय पार्षद, जलकार्य समिति के प्रभारी और निगम के कर्मचारियों की भूमिका को भी खंगाला गया है।

सुनवाई से एक दिन पहले सोमवार को याचिकाकर्ता प्रभात पांडेय ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया के माध्यम से हाई कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया।

आवेदन में याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उसकी प्रति सभी याचिकाकताओं को उपलब्ध कराई जाए। इस पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया।

अस्पतालों में भी मिला ई-कोलाई

आवेदन में याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन के अनुसार भागीरथपुरा के नलकूपों में मानव और पशुओं के मल-मूत्र में पाए जाने वाले ई-कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हुई थी। यही ई-कोलाई बैक्टीरिया कुछ शासकीय अस्पतालों के पानी में भी पाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शासकीय अस्पतालों में रोजाना हजारों की संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पतालों के पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया का पाया जाना यह दशार्ता है कि नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन अब भी गंभीर नहीं है। मजबूरी में मरीजों को पैक्ड पानी खरीदना पड़ रहा है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि शासकीय अस्पतालों की छवि खराब करने, निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाने और पैक्ड पानी बनाने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर इस तरह की लापरवाही की जा रही है।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।